नई दिल्ली
शुक्रवार
27 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 84
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



संविधान भारत की एकता, अखंडता, न्याय और...पेज-05

DELHIN/2014/58158

एमएमडीआर संशोधन बिल लागू होने से झारखंड को...पेज-08

एक नजर

भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के साथ मौजूदा खतरों से निपटने की तैयारी जरूरी : राजनाथ

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरते जोखिमों का अंदाजा लगाने, दूसरे हालातों की जांच करने और भविष्य के सुरक्षा माहौल के लिए संस्थानों को तैयार करने की अपील की है। साथ ही बदलते जियोपॉलिटिकल हालात और युद्ध के बदलते तरीके से पैदा होने वाले खतरों का असरदार जवाब देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, लंबी जमीनी सीमाएं, समुद्री हित और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियां मुश्किल में डालती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आगे की सोच वाला नजरिया जरूरी हो गया है। नई दिल्ली में गुरुवार को 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) कोर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टकराव के बदलते तरीके ने सुरक्षा माहौल को और भी मुश्किल बना दिया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पारंपरिक मिलिट्री खतरे साइबर हमलों, गलत जानकारी, आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और हाइब्रिड युद्ध के दूसरे तरीकों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा और शांति और संघर्ष के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीसी रक्षा बलों, सिविल सेवाओं और दोस्त देशों के सीनियर अधिकारियों के मिलकर काम करने के अनुभव और दिमागी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए एक कीमती प्लैटफ़ॉर्म देता है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी बनाने में सीधे योगदान देने के लिए इस दिमागी काबिलियत का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि एनडीसी रक्षा मंत्रालय के साथ सलाह करके हर कोर्स के दौरान गहराई से जांच के लिए कुछ जरूरी आज की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करने के लिए एक सिस्टम बनाए। उन्होंने कहा कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक पड़ोस, बॉर्डर मैनेजमेंट, समुद्री सुरक्षा, जरूरी टेक्नोलॉजी, आर्थिक सुरक्षा, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और बढ़ते अंदरूनी और बाहरी खतरों से जुड़े हो सकते हैं।

देशभर में विरोध-प्रदर्शनों के लिए एसओपी बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। देशभर में सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों और सभाओं के नियमन के लिए एक समान दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार तथा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकीलों के संगठन 'लॉयर्स वॉयस' की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि अनियंत्रित विरोध-प्रदर्शनों के कारण न केवल आम जनजीवन और यातायात बाधित होता है, बल्कि अदालतों के कामकाज और वकीलों की आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ता है। याचिका के अनुसार देशभर में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के संचालन के लिए एक समान और बाध्यकारी एसओपी तैयार की जाए। प्रदर्शन के आयोजकों और उसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारियां तय की जाएं।

समय पर न्याय मिलना, न्याय की अवधारणा का अनिवार्य अंग है: राष्ट्रपति

भारत की राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुईं

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज, 26 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर, 1949 को भारत के लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत किया। वर्ष 2015 में, हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर, आज के दिन को प्रति वर्ष, संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। यह संविधान के महान शिल्पकार और संविधान के आदर्शों को श्रद्धा के साथ स्मरण करने का दिन है।



राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गणतंत्र की गौरवशाली यात्रा में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं निचले न्यायालयों ने अमूल्य योगदान दिया है। पिछले दशकों के दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में कल्पनातीत बदलाव आए हैं। विशेषकर, प्रौद्योगिकी और मीडिया का प्रभाव निरंतर अधिक व्यापक और गहरा होता जा रहा है। बदलती परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हुए न्यायपालिका ने न्याय के मूल आदर्शों को सुदृढ़ बनाए रखा है। समय-समय पर भारत की न्यायपालिका ने न्यायिक जवाबदेही पर विशेष बल देकर संविधान निर्माताओं के आदर्शों को फलीभूत किया है। न्यायिक स्वतंत्रता तथा न्यायिक जवाबदेही का समन्वय न्यायपालिका की भूमिका को शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि समय पर न्याय मिलना, न्याय की अवधारणा का अनिवार्य अंग है। समय पर न्याय सुलभ कराने के लिए न्यायपालिका द्वारा पद्धतियों को सरल बनाने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा विशेष न्यायालयों का गठन करने जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह उल्लेख किया कि इन प्रयासों के बावजूद, लंबित मामलों की विशाल संख्या हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका के प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बल पर, इस चुनौती का समाधान किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि सबके पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारे संविधान का निर्देश है कि नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाकर, समान अवसर के आधार पर, न्याय सुलभ कराया जाए। इस निर्देश का यह लक्ष्य है कि आर्थिक या अन्य किसी विवशता के कारण कोई भी नागरिक, न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात में निहित है कि प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने और सफल होने के समान अवसर मिलें। उन्होंने प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच के महत्व को रेखांकित किया। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लोगों के लिए कानूनी पैरवी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में जिला, राज्य और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों को और अधिक प्रयास करके, कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में विधिक शिक्षा में समानुभूति और नैतिकता को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कानूनों के अध्ययन को दिया जाता है। उन्होंने विधि-जगत की प्रतिष्ठित विभूतियों से आग्रह किया कि वे युवा अधिवक्ताओं के समक्ष प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को यह देखना चाहिए कि इस पेशे में उत्कृष्टता के साथ समानुभूति और दक्षता के साथ करुणा का समन्वय किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के रूप में महिलाओं की अधिक व्यापक और सक्रिय भागीदारी से हमारा समाज अधिक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, समतामूलक और समावेशी बन सकेगा। न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं का दृष्टिकोण समावेशिता, विविधता और संतुलन को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया।

लोकसभा की बैठक 30 नवम्बर और राज्यसभा की दो दिसम्बर को



नई दिल्ली,एजेंसी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक क्रमश: 30 नवम्बर और दो दिसम्बर से पुन: बुलाने का अनुरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि जरूरी सरकार कामकाज निपटाने के लिए सदन की बैठक 30 नवम्बर को पुन: आहूत की जाए। इसी तरह राज्यसभा के सभापति से सदन की बैठक दो दिसम्बर को बुलाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की बैठकें कामकाज को देखते हुए तीन दिसम्बर तक चल सकती हैं।

श्री रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा को 30 नवम्बर से और राज्यसभा को दो दिसम्बर से पुन: आहुत करने का अनुरोध किया है। कामकाज को निपटाने के आधार पर दोनों सदनों की बैठक तीन दिसम्बर तक चल सकती है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि इन बैठकों में क्या जरूरी कामकाज निपटाया जायेगा लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन बैठकों के दौरान परिसीमन विधेयक तथा महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की कोशिश कर सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था। इस तरह दोनों सदनों की ये बैठकें मानसून सत्र का ही विस्तार होंगी। आमतौर पर मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कुछ दिन बाद सत्रावसान कर दिया जाता है और नवम्बर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है।

सत्रावसान करने के बाद नए सत्र के लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है लेकिन इस बार मानूसन सत्र का सत्रावसान न किए जाने की वजह से राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। विपक्ष मानसून सत्र का सत्रावसान न किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा है और इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करार देता रहा है। विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। विपक्ष लगातार यह भी कहता रहा है कि सरकार परिसीमन विधेयक तथा महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को जोड़ तोड़ से पारित कराने के लिए अचानक संसद की बैठक बुलाना चाहती है इसीलिए मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है। सरकार गत अप्रैल में परिसीमन विधेयक लोकसभा में लाई थी लेकिन इसके विपक्ष की एकजुटता के कारण मतविभाजन में विधेयक गिर गया था।

सपा के घोषणा पत्र में 25 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्जमाफी और 5 हजार बेरोजगारी भत्ते का वादा

लखनऊ,एजेंसी। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में रोजगार, किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं की सुरक्षा, श्रमिकों के कल्याण, बुनियादी ढांचे और शासन से जुड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें पार्टी के 'पीडीए' (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) एजेंडे पर खास जोर दिया गया है।



पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने, बेरोजगार स्नातकों को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता देने, किसानों का कर्ज तुरंत माफ करने और 23 फसलों तथा दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया है। 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रण पत्र-जन-मन का घोषणापत्र 2027' नाम से तैयार इस घोषणापत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 26,000 प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने और 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना को दोबारा शुरू करने का भी वादा किया गया है। रोजगार, सपा के घोषणापत्र का मुख्य हिस्सा है। 25 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा, पार्टी ने पांच वर्षों में अन्य क्षेत्रों में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है। जब तक स्नातकों को कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। भर्ती में होने वाली देरी और गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, पार्टी ने सरकारी रिक्तियों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर का प्रस्ताव रखा है। जिन भर्तियों में केवल एक चरण की परीक्षा होती है, उन्हें तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा, जबकि कई चरणों वाली भर्तियों को छह महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

राधाकृष्णन ने सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में जारी किए संविधान के नए संस्करण

नई दिल्ली,एजेंसी। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में भारत के संविधान के सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अद्यतन संस्करण जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी अनुसूचित भाषाओं में संविधान की उपलब्धता 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रतिबिंबित करती है और देश की भाषाई विविधता तथा लोकतांत्रिक समावेशिता का उत्सव है।



उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान को नागरिकों की मातृभाषा में उपलब्ध कराने से वे अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इससे शासन और नागरिकों के बीच दूरी कम होगी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और मजबूत होगी। उन्होंने इस अवसर को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताते हुए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की जीवंत आत्मा है। उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से संविधान को आम लोगों के और करीब लाने में मदद मिलेगी। यह भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान भारतम और काशी तमिल संगमम जैसी पहल भारत की सभ्यतागत विरासत को सुरक्षित रखने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

दिल्ली में भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक आज से, 2027 चुनावों पर होगा मंथन

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी 27 और 28 नवंबर को दिल्ली में पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक आयोजित करने जा रही है। दिल्ली के पूसा परिसर में होने वाली इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, पार्टी की भविष्य की रणनीति और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे।



इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के सभी 107 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, राज्यों में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर रणनीति तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा। भाजपा की इस बैठक का सबसे अहम एजेंडा वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत चुनावी राज्यों में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति, चुनावी रणनीति और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों में पार्टी के कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश नेतृत्व के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन यानी 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करने की संभावना है। प्रधानमंत्री का संबोधन आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उप्र में सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएंगे: खरगे

एसआईआर के जरिए दलित-पिछड़ों के वोट काटने की साजिश कर रही भाजपा

लखनऊ,एजेंसी। संविधान दिवस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरूवार को लखनऊ पहुंचकर आन्दोलन का नेतृत्व किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए दलित-पिछड़ों के वोट काटने की साजिश भाजपा कर रही है। वो भूल गए हैं कि वोट जनता की ताकत है, किसी सरकार की जागीर नहीं। कुछ दिन पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अचानक समझ आया कि वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने खूब शोर मचाया कि हिंदुओं के वोट कट गए। हाँ, वोट काटे गए हैं - दलितों, अति पिछड़ों और वंचितों के वोट काटे हैं, जिन्होंने 2024 लोक सभा चुनाव में मोदी को यू0पी0 में हराया था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान बदलने की कोशिश को रोक दिया था। अब यही लोग उत्तर प्रदेश की सरकार बदलकर काँग्रेस-सपा गठबंधन की सरकार बनाएँगे।



कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का अहंकार 2024 में उत्तर प्रदेश ने ही तोड़ा था। 2026 में एम0एल0सी0 चुनाव में मोदी जी के ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटें भाजपा हार गई। मोदी ने अपनी नीतियों की विफलता खुद स्वीकार कर ली है। भाजपा अब चंद दिनों की मेहमान है। मोदी को समझ नहीं आ रहा कि देश कैसे चलाएं। अब तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं, वो ना रोजगार दे रहे हैं और ना ही निवेश कर रहे हैं। यह हम सालों से कहते आ रहे है, पर इन्होंने कभी हमारी बात नहीं मानी। उन्होने कहा कि हमारे संविधान ने शुरू से ही दलितों, महिलाओं, गरीबों और वंचित वर्गों को वोट का अधिकार दिया। जबकि कई शक्तिशाली देशों ने महिलाओं और कमजोर तबकों को कई वर्षों तक वोट नहीं करने दिया था। श्री खरगे ने कहा कि आरएसएस इस संविधान के खिलाफ थी और अब भी है। इतिहास गवाह है कि जब से संविधान बना, आरएसएस के नेताओं ने इसका भारी विरोध किया। ये संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। खड़गे ने कहा कि डबल इंजन सरकार रोजगार का हर रास्ता खत्म कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के बच्चे फौज में सम्मान की पक्की नौकरी और पेंशन पाते थे। मोदी ने इसे अग्निवीर के नाम पर टेंपरोरी बना दिया। केवल 4 साल की नौकरी। अभी दो साल का एक्सटेंशन चुनाव के कारण दिया है। ये एक-एक करके रोजगार का हर रास्ता को बंद कर रहे हैं।

संविधान की प्रति लेकर घूमने वाले राहुल गांधी पहले उसकी मूल भावना समझें: अमित शाह

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें संसद की लाइब्रेरी में जाकर संविधान की मूल प्रति और उसमें बने चित्रों को देखना चाहिए, ताकि वे उसकी मूल भावना को समझ सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का उपहास करते हैं और संसद में चर्चा करने के बजाय सड़क पर बहस की बात करते हैं। दिल्ली भाजपा की ओर से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में आयोजित 'संविधान गौरव दिवस' समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि संसद का निर्माण ही चर्चा करने के लिए किया गया है लेकिन राहुल गांधी संसद में चर्चा नहीं चाहते और सड़क पर बहस की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम करने, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाने और विदेशों में भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही लेकिन उसने कभी सड़क पर बहस की मांग नहीं की, अदालतों के बारे में अनर्गल बातें नहीं कीं और न ही चुनाव आयोग का अपमान किया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह नकारना संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। कांग्रेस नेता पर तंज



कसते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'राहुल जी का प्रॉब्लम यह है कि 20 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं। जब से वह आए, एक भी विजय भाग्य में नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के लिए चुनाव प्रक्रिया को दोष देने के बजाय राहुल गांधी को जनता का विश्वास जीतना चाहिए, देश की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके समाधान लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। शाह ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि देश में सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं होने के बावजूद वह हर तीसरे महीने छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं लेकिन उनकी पार्टी का इतिहास आपातकाल से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान 18 महीने तक संविधान की मूल भावना को बंद करके रखा और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित किया। अमित शाह ने कहा कि संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की आकांक्षाओं, संघर्ष और बलिदान का दस्तावेज है। वर्ष 1857 से 1947 तक चले स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और कई लोगों ने अपना घर-बार, व्यापार, करियर तथा पढ़ाई छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के इन मूल्यों और आकांक्षाओं को संविधान में स्थान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को केवल पुस्तक के रूप में देखने से उसकी मूल भावना को नहीं समझा जा सकता। इसके मूल तत्वों और भावना को समझने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं, देश की संस्कृति और उन मूल्यों को जानना होगा, जिनके आधार पर संविधान की रचना हुई। संविधान ने देश को एक ऐसा कानूनी ढांचा दिया, जिसके माध्यम से गुलामी के लंबे दौर में खोए मूल्यों को फिर से स्थापित करने का रास्ता तय किया गया। शाह ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सत्ता जनता के हाथ में सौंपी और यह अधिकार दिया कि वह तय करे कि किसे शासन करना है। साथ ही, सत्ता में आने वालों के लिए यह व्यवस्था की कि उन्हें संविधान की मर्यादाओं में रहकर शासन चलाना होगा। संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संविधान को केवल शासन चलाने की मार्गदर्शिका के रूप में देखने का प्रयास हुआ और उसकी मूल भावना को किशोरों, युवाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, ताकि संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

बाबा साहेब के दूरदर्शी विचारों से प्रेरणा लेकर जनकल्याण के संकल्प को साकार करना हमारा ध्येय : रविन्द्र इन्द्राज सिंह

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने गुरुवार को कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर अंत्योदय, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के संकल्प को साकार करना उनका ध्येय है। इस अवसर पर मंत्री ने दिल्ली सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा, 'समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना और वंचित वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता और न्याय का सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। अंबेडकर ने ऐसे भारत की परिकल्पना की थी, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। उनके दूरदर्शी विचार आज भी सामाजिक न्याय, समरसता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

इन्द्राज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बाबा साहेब की विरासत को सम्मान देने तथा उनके जीवन और विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। पंचतीर्थों का विकास इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो बाबा साहेब के राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान को सम्मानित करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना तथा प्रत्येक नागरिक को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। मंत्री ने सभी नागरिकों से संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही समतामूलक, सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण का आधार है।

दिल्ली विधानसभा के बाहर 18 दिसंबर को प्रदर्शन करेगा लोकतंत्र सेनानी संघ

नई दिल्ली। दिल्ली के लोकतंत्र सेनानियों की लंबित मांगों को लेकर लोकतंत्र सेनानी संघ 18 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन होने वाले इस प्रदर्शन में संघ के पदाधिकारी और लोकतंत्र सेनानी मुंह पर काली पट्टी बांधकर तथा हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगें रखेंगे।

प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय सह संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बब्बर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा और दिल्ली प्रदेश महामंत्री राज कुमार सापरा सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी शामिल होंगे। अश्विनी कुमार चौबे के दिल्ली आवास पर गुरुवार को आयोजित संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में दिल्ली के लोकतंत्र सेनानियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर मासिक सम्मान निधि प्रदान करने, उन्हें सम्मान पत्र एवं ताम्रपत्र से सम्मानित करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग करने का फैसला किया गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों ने यातनाएं झेलीं और अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए योगदान दिया।

दिल्ली में 27 नवंबर से सजेगा 'कारीगर बाज़ार'

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आगामी शुक्रवार से 10 दिवसीय 'कारीगर बाज़ार' का दूसरा संस्करण शुरू होगा। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक कला और हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा देना है। क्राफ्ट एंड आर्टिजन रिवाइवल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 26 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 250 से अधिक कारीगर तथा शिल्पकार हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार एवं संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकारों के साथ-साथ जीआई टैग प्राप्त कला के विशेषज्ञ, पारंपरिक बुनकर, महिला कारीगर, स्वयं सहायता समूह और उभरते उद्यमी शामिल होंगे।

बाज़ार में आगंतुकों को देश के विभिन्न हिस्सों की हस्तनिर्मित कलाकृतियों और पारंपरिक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इनमें मुख्य रूप से वस्त्र एवं कढ़ाई में बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी, इकत, ब्लॉक प्रिंटिंग, चिकनकारी और कच्छ कढ़ाई,



चित्रकला एवं शिल्प में मधुबनी एवं गोंड चित्रकला, टेराकोटा, ब्लू पॉटरी और धातु एवं लकड़ी की नक्काशी, अन्य उत्पादों में पारंपरिक आभूषण और पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) हस्तशिल्प शामिल हैं। इस संस्करण में 'कारीगर एक्सपीरियंस सेंटर' विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां आने वाले लोग बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, चित्रकला और नक्काशी जैसी पारंपरिक कलाओं का लाइव प्रदर्शन देख सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को उत्पादों के साथ-साथ उनके पीछे की तकनीक और कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत से रूबरू कराना है। कारीगर बाज़ार के निदेशक एवं सह-संस्थापक आमिर खान ने बताया कि पहले संस्करण की शानदार सफलता के बाद इस बार आयोजन को और बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को पहचान दिलाना और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना है। वहीं, निदेशक एवं सह-संस्थापक पंकज सिंह राणा ने कहा कि इस पहल के जरिए देश की विविध शिल्प परंपराओं को व्यापक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से लेकर छोटे कारीगर समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों तक, सभी को अपनी कला प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माता अमृतानंदमयी देवी 'अम्मा' से की मुलाकात, अमृतश्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का किया शुभारंभ



नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ब्रह्मस्थानम् महोत्सव में माता अमृतानंदमयी देवी 'अम्मा' से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमृतश्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ब्रह्मस्थानम् महोत्सव में माता अमृतानंदमयी देवी 'अम्मा' का सान्निध्य और आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अम्मा का जीवन 'सेवा परमो धर्म:' की सनातन संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतश्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने कहा कि देश के 21 राज्यों में 15 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाखों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अम्मा का सेवा कार्य अत्यंत प्रेरणादायी है। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक शिखा राय, गजेंद्र यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

दिल्ली विश्वविद्यालय 12 से 14 फरवरी तक दूसरे साहित्य महोत्सव का करेगा आयोजन

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे साहित्य महोत्सव (डीयूएलएफ 2.0) का आयोजन 12 से 14 फरवरी, 2027 तक किया जाएगा। इसका निर्णय डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साहित्य महोत्सव कमेटी की बैठक में गुरुवार को लिया गया। महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजित इस पहली बैठक में साहित्य महोत्सव के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित डीयू के पहले साहित्य महोत्सव का आयोजन बहुत सफल रहा था। उन्होंने आशा जताई कि इस बार का आयोजन और भी विशाल होगा।

कुलपति ने डीयूएलएफ 2.0 के आयोजन को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, साहित्य महोत्सव के दौरान उन्हें भी सम्मान दिया जाए। उन्होंने कहा कि साहित्य महोत्सव के आयोजन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण विभागों की भागीदारी भी आयोजन में



सुनिश्चित की जाए। कुलपति ने कहा कि साहित्य महोत्सव का आयोजन देश हित को ध्यान में रख कर होने चाहिए। आयोजन में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए, जो सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र हित के खिलाफ हो। इस अवसर पर कमेटी सदस्यों ने आगामी आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। साहित्य महोत्सव कमेटी की अध्यक्ष प्रो. रजनी अब्बी ने बैठक में सभी का स्वागत किया। साहित्य महोत्सव के कनवीनर और उपाध्यक्ष अनूप लाठर ने पिछले वर्ष हुए डीयूएलएफ़ 1.0 के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने डीयूएलएफ 2.0 के आयोजन की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर के नामी लेखक, कवि, मीडिया जगत के लोग और साहित्य से जुड़ी जानी मानी हस्तियां भागीदारी करेंगी। इस दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

नशामुक्त युवा ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव: विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि नशामुक्त युवा ही सशक्त, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक आधारशिला हैं।

विजेन्द्र गुप्ता ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में आयोजित 'नशामुक्त युवा अभियान' जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'जब युवा नशे को अस्वीकार करते हैं, तो वे अनुशासन, उद्देश्यपूर्ण जीवन और नेतृत्व से भरे भविष्य का चयन करते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल 'मेरा युवा भारत' के तहत दिल्ली के विभिन्न जिलों से आए 250 युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान परिसर में 'दिल्ली अगेंस्ट ड्रग्स' के संदेश लिखे गुलाबी गुब्बारे भी आकाश में छोड़े गए। सदन में युवाओं से संवाद करते हुए गुप्ता ने उनसे 'विरासत भी, विकास भी' के सिद्धांत के साथ 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध दिल्ली और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं में जागरूकता, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली बेहद जरूरी है।

विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत सभी 250 प्रतिभागियों को परिसर का निर्देशित भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्रों ने ऐतिहासिक सदन कक्ष और विधानसभा पुस्तकालय का दौरा किया तथा भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पर आधारित विशेष वृत्तचित्र देखे। विधानसभा की ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष ने बताया कि इस परिसर को एक धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित और विकसित किया जा रहा है।

पूर्व सांसद आनंद मोहन की डीएम हत्याकांड में समयपूर्व रिहाई रद्द, एक महीने में सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1994 में आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार सरकार के अप्रैल 2023 के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके तहत आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार जेल मैनुअल में किए गए बदलाव को 'मनमाना' और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इस संशोधन के जरिए ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर लगी रोक हटा दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल दोषी के अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज के अधिकारों की भी रक्षा करता है। दिसंबर 1994 में बिहार के मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन के नेतृत्व में निकल रहे एक जुलूस के दौरान भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने साल 2007 में इस मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2008 में पटना उच्च न्यायालय ने उम्रकैद में बदल दिया और 2012 में उच्चतम न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। 14 साल से अधिक की सजा काटने के बाद बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर अप्रैल 2023 में उन्हें रिहा कर दिया था, जिसे उमा कृष्णैया ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

संविधान दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने निकाला संविधान बचाओ मार्च

नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में संविधान बचाओ मार्च निकाला। मार्च पटेल चेस्ट से प्रारंभ होकर आर्ट्स फैकल्टी गेट तक निकाला गया। इस मार्च में एनएसयूआई के पदाधिकारियों, छात्र नेताओं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस मार्च के माध्यम से एनएसयूआई ने संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि पांडेय ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान की रक्षा करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले हर प्रयास के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

आबकारी घोटाला : केजरीवाल समेत 23 आरोपितों को बरी करने के फैसले को सीबीआई ने दी चुनौती

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपितों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 और 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए।

सीबीआई ने कहा कि आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस मामले को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। सीबीआई के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई गंभीर कमियां हैं, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सबूतों का मूल्यांकन किया और एक तरह से मिनी ट्रायल चलाया। उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी



आरोपितों को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास है। न्यायालय ने कहा कि हजारों पेजों की चार्जशीट में पेश किये गए तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे। केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत दी।

ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया। न्यायालय ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त को के. कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई, 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

एक नजर

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में सात एसीपी के तबादले

नोएडा। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर ने कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सात सहायक पुलिस आयुक्तों को नई तैनाती दी है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने गुरुवार को बताया कि पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर आज एसीपी स्तर के सात पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि आईपीएस अधिकारी संचित शर्मा को सहायक पुलिस आयुक्त-प्रथम ग्रेटर नोएडा से सहायक पुलिस आयुक्त -द्वितीय सेंट्रल नोएडा, डॉ रवि शंकर को सहायक पुलिस आयुक्त -तीन ग्रेटर नोएडा से सहायक पुलिस आयुक्त- प्रथम नोएडा, सिद्धार्थ गौतम को सहायक पुलिस आयुक्त-प्रथम सेंट्रल नोएडा, कमलेश कांत को सहायक पुलिस आयुक्त- तीन सेंट्रल नोएडा, अनुराग कुमार सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त- प्रथम ग्रेटर नोएडा, शिवनारायण वैश्य को सहायक पुलिस आयुक्त- तृतीय ग्रेटर नोएडा तथा दीपांशी राठौर को सहायक पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा बनाया गया है।

फरीदाबाद की बेटी सिया सोरौत ने ताइक्वांडो टूर्नामेंट में जीता गोल्ड मेडल

फरीदाबाद। शहर की होनहार बेटी सिया सोरौत ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल के प्रति समर्पण का शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर फरीदाबाद और हरियाणा का नाम रोशन किया है। सिया ने 24 नवंबर 2026 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट के सब-जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राहुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छठी कक्षा की छात्रा सिया ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन में खुशी का माहौल है। सिया की सफलता को शहर के लिए भी गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सिया की इस कामयाबी ने एक बार फिर साबित किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिलें तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। सिया की उपलब्धि अन्य बच्चों, विशेषकर बेटियों के लिए भी प्रेरणादायक है। उनकी सफलता पर परिजनों और शुभचिंतकों ने खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

शवगृह पर डेढ़ घंटे तक लटका रहा ताला, शव लेकर भटकती रही महिला एएसआई

फरीदाबाद। बादशाह खान नागरिक अस्पताल (बीके अस्पताल) की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार रात ट्रेन की चपेट में आए एक युवक का शव लेकर पहुंची जीआरपी की महिला एएसआई को शवगृह के बाहर करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शवगृह के गेट पर ताला लगा था और कर्मचारियों के पास चाबी तक उपलब्ध नहीं थी। आखिरकार हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने पत्थर से ताला तोड़कर गेट खुलवाया। जीआरपी की महिला एएसआई सुदेश के अनुसार, बुधवार शाम ओल्ड रेलवे स्टेशन पर सुशासन एक्सप्रेस की चपेट में आने से 32 वर्षीय पवन की मौत हो गई थी। वह अपने फूफा को ट्रेन में छोड़ने आया था। हादसे के बाद पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रात अस्पताल लेकर पहुंची। यहां शवगृह पर ताला लगा मिला। कर्मचारियों को चाबी तलाशने के लिए कहा गया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक चाबी नहीं मिली। रात हाउसकीपिंग कर्मचारी संदीप और बलबीर पहुंचे, पर उनके पास भी चाबी नहीं थी। आखिरकार दोनों ने पत्थर से ताला तोड़कर शवगृह का गेट खोला और शव को अंदर रखवाया। इस मामले में बीके अस्पताल के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और शव रखवाने के बाद अस्पताल की जिम्मेदारी शुरू होती है। हालांकि, डेढ़ घंटे तक शवगृह पर ताला लगे रहने और चाबी नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

साइबर अपराध में बाप-बेटा गिरफ्तार, बेटे पर सेक्सटॉर्शन का आरोप

नूंह। नूंह जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए पुन्हाना की टीम ने अलग-अलग मामलों में बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बेटे पर सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप है, जबकि पिता आईटी एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी था और उसकी गिरफ्तारी पर एक हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि पहले मामले में सीआईए पुनहाना की टीम ने जुनैद निवासी गांव मड़ियाकी, थाना बिछोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ साइबर थाना नूंह में सेक्सटॉर्शन से संबंधित मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें तीन सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी अनजान पुरुषों से संपर्क कर सेक्सटिंग के बहाने बातचीत शुरू करता था। इसके बाद वीडियो कॉल के दौरान पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल कर वास्तविक बातचीत का भ्रम पैदा करता था।

विकास कार्यों में देरी, गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं : डॉ. पंकज



गुरुग्राम,एजेंसी। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. पंकज ने स्पष्ट किया है कि शहर में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही अथवा गुणवत्ता के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो।

निगमायुक्त गुरुवार को अपने कार्यालय में इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में चीफ इंजीनियर विजय ढाका सहित अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता उपस्थित रहे। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जूनियर इंजीनियर अपने-अपने वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता भी समय-समय पर मौके पर जाकर कार्यों की जांच करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य का एस्टीमेट तैयार करने से पहले संबंधित साइट का पूरी तरह निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां किसी प्रकार का विवाद या अतिक्रमण न हो। निगमायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों के एस्टीमेट में पूरी सटीकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों का चयन और क्रियान्वयन सही तथ्यों एवं जरूरतों के आधार पर किया जाए, ताकि नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। सडक़ निर्माण के दौरान सीएक्यूएम के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि धूल और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी न हो। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य को पूरा तभी माना जाएगा, जब वह पूरी तरह उपयोग योग्य हो। कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित पार्षद का संतुष्टि-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंसी निर्धारित समय-सीमा के बाद भी कार्य लंबित रखती है या गुणवत्ता के अनुरूप काम नहीं करती है, तो ऐसी एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए।

एसटीएफ ने पकड़ी 70 लाख के गांजे की खेप, दो तस्कर भी काबू

गुरुग्राम। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की सेंट्रल यूनिट ने सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक गांव सांचोली में गुरुवार को एक ट्रक से करीब 371.680 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की बाजार में खुदरा कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गांजे की यह खेप ओडिशा से लेकर आए थे और इसे राजस्थान में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की कडिय़ां जोडऩे में जुटी है।एसटीएफ की सेंट्रल यूनिट को सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए नशीले पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बुधवार देर शाम टीम ने सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर गांव सांचोली के पास नाकाबंदी कर राजस्थान नंबर के एक ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर ट्रक में रखे 19 कट्टों से 371.680 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद टीम ने ट्रक में सवार दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनकी पहचान राजस्थान के चूरू निवासी सज्जन और राम सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे की यह खेप ओडिशा से लेकर आए थे और इसे राजस्थान में सप्लाई किया जाना था। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की खुदरा बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की बरामदगी के बाद एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा खेप किसके पास पहुंचाई जानी थी।मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुग्राम में निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की मांग

गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण कम करने के सरकार के प्रयासों के बीच अब गुरुग्राम में निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना को लागू करने की मांग उठी है। आईओन गुरुग्राम संस्था की ओर से इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। गुरुग्राम में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने का आईओनगुरुग्राम संस्था ने अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि बच्चों को स्कूल छोडऩे और वापस लाने, रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों के लिए बाहर जाने, ऑफिस आने-जाने और इसी तरह की अन्य निजी यात्राओं से शहर में वाहनों की आवाजाही बढ़ती है।

वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) की व्यवस्था होने के बावजूद, इस तरह की कई यात्राएं जारी रहती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है, वाहन लंबे समय तक चालू हालत में खड़े रहते हैं और प्रदूषण (उत्सर्जन) भी बढ़ता है। इसलिए ऑड-ईवन योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अंक के आधार पर तय दिनों में ही उन्हें सडक़ पर चलाने की अनुमति होगी। इसमें कुछ जरूरी छूट का भी प्रावधान होगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ इन दोनों उपायों को लागू करने से वाहनों की आवाजाही और उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करने में अधिक व्यापक और प्रभावी मदद मिल सकती है। संगठन ने यह भी माना कि ऐसा कदम तभी संभव हो पाएगा, जब इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाए।

सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय हो और छूट के प्रावधान भी सोच-समझकर तय किए जाएं। संगठन ने आगे कहा कि यह योजना तभी बेहतर तरीके से काम करेगी, जब इसके साथ सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इससे लोग निजी वाहनों पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकेंगे। आईओनगुरुग्राम के फाउंडर डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी ने कहा कि वाहनों से प्रदूषण एक ऐसा क्षेत्र है जहां केंद्रित प्रयासों से कुछ बदलाव लाया जा सकता है। हमारा मानना है कि वर्क फ्रॉम होम और ऑड-ईवन दो ऐसे उपाय हैं, जो एक-दूसरे के पूरक हैं। एक तो बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही कम होगी, जबकि दूसरा शहर के भीतर पहले से चल रहे ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

योगी आदित्यनाथ की माता जी को जिलाधिकारी ने दी श्रद्धांजलि

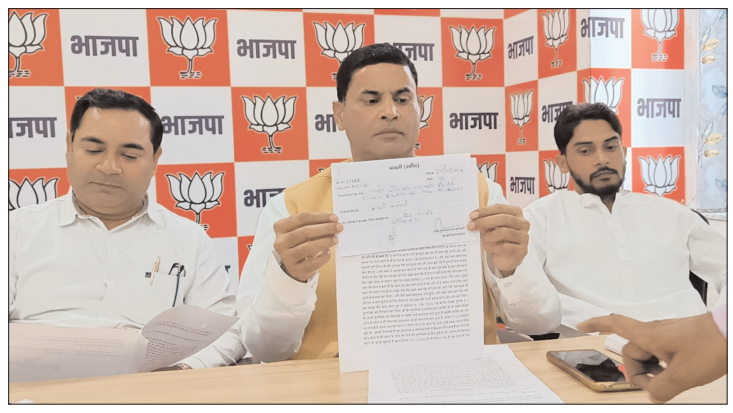
अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



बागपत। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी सावित्री देवी के निधन पर गुरुवार को बागपत के जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल और पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने भगवानपुर नांगल स्थित श्री शिव गोरखनाथ मठ पहुंच कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों अधिकारियों ने दिवंगत सावित्री देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की।

श्रद्धांजलि के दौरान अधिकारियों ने कहा कि मां का स्नेह, त्याग और आशीर्वाद परिवार के लिए अनमोल होता है। उनके निधन से हुई क्षति अपूरणीय है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मठ परिसर एवं आश्रम का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 400 वर्ष पुरानी तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध श्री शिव गोरखनाथ मठ बागपत की प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। यहां बाबा छोटेनाथ और बाबा लिच्छीनाथ की समाधियां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र हैं। मठ परिसर में कई मंदिर और धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। आश्रम के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से यहां विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए गए हैं। अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखा।

पांच करोड़ की रंगदारी मामले में भाजपा नेता ने विधायक व भाई के खिलाफ दी शिकायत



नूंह। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन से लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। भाजपा नेता जाहिद हुसैन ने नूंह विधायक आफताब अहमद और उनके छोटे भाई मेहताब अहमद के खिलाफ नूंह सिटी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

जाहिद हुसैन ने आरोप लगाया है कि रंगदारी मामले में सामने आए चौथे व्यक्ति को बचाने के लिए विधायक आफताब अहमद प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उक्त व्यक्ति को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी बताया है। हालांकि, विधायक और उनके भाई पर लगाए गए आरोपों की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है। भाजपा नेता जाहिद हुसैन ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी एक व्यक्ति ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी। उनके अनुसार, धमकी दिलवाने में बाई गांव के एक व्यक्ति की भूमिका है, जबकि इस मामले का मुख्य आरोपी पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। पुलिस अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, गिरफ्तार आरोपी मुकीम ने पूछताछ के दौरान आबिद, रहीश, शकील और वसीम के नाम बताए हैं। जाहिद हुसैन का आरोप है कि मामले में चौथे व्यक्ति का नाम सामने आने के बाद विधायक आफताब अहमद उसे बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है, वही इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है। भाजपा नेता के मुताबिक, दो दिन पहले दीहाना गांव में एक शादी समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद से उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान विधायक ने उनसे सवाल किया कि रंगदारी मामले में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। इस पर जाहिद हुसैन ने जवाब दिया कि आरोपियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें इस मामले में विधायक की भूमिका पर संदेह हो रहा है। गौरतलब है कि 27 सितंबर को भाजपा नेता जाहिद हुसैन को लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए फोन पर धमकी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस की ओर से अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब विधायक और उनके भाई के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद इस प्रकरण में नया विवाद खड़ा हो गया है।

गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार

साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में बांग्लादेशी नागरिकों के काम करने की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने नौ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन सभी से खोड़ा थाने में पुलिस समेत खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारी इस विषय में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं।

खोड़ा थाना पुलिस को क्षेत्र में एक गारमेंट फैक्ट्री में कुछ बांग्लादेशियों के काम करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापामारी की और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इनके पकड़े जाने की सूचना के बाद एलआइयू समेत अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हुई और संयुक्त रूप से इनसे पूछताछ चल रही है। इन सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और फैक्ट्री में इन्हें रखवाये जाने वाले ठेकेदार से भी पूछताछ चल रही है।

तीन मौतों के बाद भी नहीं जागा सिस्टम, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बेखौफ दौड़ रहे दोपहिया और रॉन्ग साइड वाहन

गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ-एक्सप्रेस वे पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना से न तो पुलिस प्रशासन ने सबक लिया और न ही लोगों ने। प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बेखौफ होकर दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा लोग फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग न करके अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे एक्सप्रेसवे पार कर रहे हैं। लालकुआं जैसे प्वाइंट पर रुपये कमाने के लालच में टैक्सी वालों ने सवारी बैठाने का अवैध स्टैंड बना लिया है। डीएमई पर दोपहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद बाइक और स्कूटर चालक बेखौफ होकर एक्सप्रेसवे पर अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ रहे हैं। तेज रफ्तार कारों और भारी वाहनों के बीच इन दोपहिया वाहनों का चलना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि अचानक इनके सामने आने से अन्य चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे पीछे आ रहे वाहनों के आपस में टकराने की आशंका हमेशा बनी रहती है। दूसरी ओर, लालकुआं जैसे व्यस्त प्वाइंट पर भी नियमों की भारी अनदेखी देखने को मिलती है, जहां मुरादाबाद की तरफ जाने वाले कुछ कार चालकों ने हाईवे के एक पूरे हिस्से को अवैध सवारी स्टैंड में तब्दील कर दिया है। यहां खुलेआम कार चालकों द्वारा सवारियों का इंतजार किया जाता है और बीच सड़क पर रखकर सामान को चढ़ाया-उतारा जाता है, जिसके चलते नोएडा की तरफ से तेज गति से आने वाले वाहनों को अचानक ब्रेक लगाने के कारण गंभीर हादसों का खतरा झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा, छिजारसी, क्रॉसिंग, लालकुआं और विजयनगर जैसे प्रमुख प्वाइंट्स पर रांग साइड में वाहन चलाने का चलन आम हो गया है। इन सभी जगहों के पास ही यू-टर्न बने हुए हैं, इसके बावजूद लोग थोड़ा सा रास्ता बचाने के लिए जोखिम भरे शार्टकट के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगा रहे हैं।

नूंह में जुटेंगे 12 देशों के 80 प्रतिनिधि, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का करेंगे अध्ययन

नूंह। मेवात के नाई नंगला गांव को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 12 देशों के करीब 80 प्रतिनिधियों का दल गांव का दौरा कर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और टीकाकरण अभियान की जमीनी हकीकत से रूबरू होगा। टीकों और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (गावी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से जुड़े प्रतिनिधियों का यह दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों एवं महिलाओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना के दिशा-निर्देशों पर विभागीय टीमें गांव में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। जिला उपायुक्त अखिल पिलानी भी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार को उप सिविल सर्जन डॉ. आशीष सिंगला के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम ने गांव का दौरा किया। टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण व्यवस्था और विभागीय गतिविधियों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपी। गुरुवार को फिरोजपुर झिरका के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार ने भी नाई नंगला गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने ग्रामीणों को प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय दौरे की जानकारी देते हुए तैयारियों के संबंध में चर्चा की। गांव की महिला सरपंच आरिशा तफज्जुल के पति तफज्जुल हुसैन ने बताया कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें गांव का निरीक्षण कर चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के गांव पहुंचने की संभावना है। प्रस्तावित दौरे के दौरान विदेशी प्रतिनिधि बच्चों और महिलाओं के नियमित टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

धूल फांक रही एंटी स्मॉग गन को ट्रैक्टर से खींचकर ले गए कर्मचारी



नूंह। नूंह शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लाखों रुपये की लागत से नगर परिषद में लाई गई एंटी स्मॉग गन कई महीनों से कार्यालय परिसर में धूल फांक रही थी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लाई गई यह मशीन नगर परिषद परिसर में सफेद हाथी बनी हुई थी। ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एंटी स्मॉग गन मशीन के लंबे समय से खड़े रहने और इसके इस्तेमाल नहीं होने के का यह स्टार्ट नहीं हो पाई इसके बाद नूंह नगर परिषद के कर्मचारियों ने एंटी स्मॉग गन मशीन को कार्यालय परिसर से बाहर निकालने की कवायद शुरू की। हालांकि, मशीन को बाहर निकालने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार ट्रैक्टर से जोड़कर एंटी स्मॉग गन को वहां से ले जाया गया। गौरतलब है कि एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हवा में पानी की महीन फुहारों का छिड़काव कर धूल के कणों को कम करने के लिए किया जाता है। खासकर प्रदूषण का स्तर बढ़ने और ग्रेप-3 जैसी पाबंदियां लागू होने के दौरान ऐसी मशीनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके बावजूद लाखों रुपये की लागत से लाई गई मशीन का कई महीनों तक नगर परिषद परिसर में खड़ा रहना और प्रदूषण बढ़ने के दौरान भी इसका इस्तेमाल नहीं होना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता रहा।

अब कर्मचारियों ने ट्रैक्टर के जरिए मशीन को परिसर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपये की लागत से खरीदी गई इस मशीन का नियमित संचालन कब शुरू होगा। क्या नगर परिषद इसे प्रदूषण नियंत्रण अभियान में शामिल कर शहरवासियों को राहत दिला पाएगी या यह मशीन आगे भी केवल कागजों और तस्वीरों तक ही सीमित रहेगी।

भारत-नेपाल संबंधः भरोसे की नई उम्मीद, चुनौतियाँ बरकरार

डॉ. प्रियंका सौरभ


© Sajjad Hussain/AFP

भारत और नेपाल के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था, सामाजिक निकटता और साझा सभ्यतागत चेतना से जुड़े हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर गंगा के मैदानों तक फैले इन संबंधों की अपनी विशिष्ट पहचान है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते, खुली सीमा, धार्मिक यात्राएं और आर्थिक निर्भरता इस साझेदारी को अन्य पड़ोसी संबंधों से अलग बनाती हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद, संधियों की समीक्षा, राजनीतिक अविश्वास और चीन की बढ़ती सक्रियता ने भारत-नेपाल संबंधों में कई जटिलताएं पैदा की हैं। ऐसे समय में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की 22-23 नवंबर की पहली राजकीय भारत यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बालेन्द्र शाह के बीच हुई बातचीत तथा 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के संयुक्त दृष्टिकोण ने यह संकेत दिया है कि दोनों देश पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप साझेदारी विकसित करना चाहते हैं। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भारत और नेपाल के संबंधों को केवल ऐतिहासिक भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग, समान सम्मान, पारस्परिक विश्वास और व्यावहारिक परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाना होगा।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 हजार करोड़ रुपये के विकास सहयोग पैकेज की घोषणा है। इसमें 3500 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और नई आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए दिए जाएंगे, जबकि 11,500 करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगस्त 2026 में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। सड़कें, पुल, घर और आजीविका के साधन बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे में भारत की आर्थिक सहायता केवल वित्तीय सहयोग नहीं बल्कि संकट के समय पड़ोसी के साथ खड़े होने का संदेश भी है। हालांकि इस सहायता की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि धनराशि समय पर उपलब्ध हो और परियोजनाएं पारदर्शिता के साथ पूरी हों। दोनों देशों ने संबंधों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति भी व्यक्त की है। वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि सहित पुराने द्विपक्षीय समझौतों की पारस्परिक सहमति से समीक्षा कर अद्यतन कानूनी ढांचा तैयार करने की बात इस यात्रा का महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष है। नेपाल में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि स्वतंत्रता के बाद बदल चुकी परिस्थितियों के अनुसार भारत के साथ संबंधों की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। नेपाल की संप्रभुता, समानता और स्वतंत्र विदेश नीति की आकांक्षाओं को समझना भारत के लिए भी आवश्यक है। किसी भी संधि का उद्देश्य दोनों देशों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष में असंतोष पैदा करना। इस दिशा में आपसी सहमति से आगे बढ़ना संबंधों को नई मजबूती दे सकता है।

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई गति देगी। जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि के रूप में प्रतिष्ठित है, जबकि अयोध्या भगवान श्रीराम की नगरी है। दोनों स्थानों के बीच सीधा रेल संपर्क धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ व्यापार और जनसंपर्क को भी बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त भारत के धारचूला और नेपाल के दार्चुला के बीच मोटर योग्य पुल का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगा। नेपाल के पारगमन व्यापार के लिए कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह तक अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध कराने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इससे नेपाल की समुद्री व्यापार के लिए भारतीय मार्गों पर निर्भरता को अधिक विकल्पों के साथ व्यवस्थित किया जा सकेगा। ऊर्जा सहयोग इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। नेपाल जलविद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं वाला देश है, जबकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता है। 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की आधारशिला इस साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण को भी जनता को समर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त झापा में पेट्रोलियम टर्मिनल और सिलीगुड़ी-झापा पाइपलाइन की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। यदि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाता है तो नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत को भी क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग का लाभ मिलेगा। शिक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सहयोग को लेकर भी सकारात्मक पहल हुई है। नेपाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का अपतटीय परिसर स्थापित करने की सहमति तथा विभिन्न क्षेत्रों में आठ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच ज्ञान और कौशल आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, अनुसंधान, प्रशासनिक प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग से संबंधों का दायरा केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम नागरिकों के जीवन तक पहुंचेगा। इन उपलब्धियों के बीच यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि भारत-नेपाल संबंधों की सबसे पुरानी और संवेदनशील समस्याओं का समाधान अभी बाकी है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर सीमा विवाद दोनों देशों के बीच अविश्वास का बड़ा कारण बना हुआ है। वर्ष 2020 में नेपाल द्वारा नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद यह विवाद गहरा गया था। इन क्षेत्रों पर दोनों देशों के अलग-अलग दावे हैं। किसी भी आर्थिक समझौते या विकास परियोजना से इस ऐतिहासिक विवाद का स्वत: समाधान नहीं हो सकता। दोनों देशों को कूटनीतिक संयम के साथ तथ्यात्मक और ऐतिहासिक आधार पर बातचीत करनी होगी। नेपाल की एक अन्य चिंता भारत के साथ व्यापार असंतुलन है। नेपाल का आयात भारत से होने वाले निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं होने के कारण नेपाल का विदेशी व्यापार भारतीय पारगमन मार्गों पर निर्भर करता है। इसलिए भारत को नेपाल के उत्पादों के लिए अपने बाजार में अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करना इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकता है।

चीन का बढ़ता प्रभाव भी इस रिश्ते की एक बड़ी चुनौती है। नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भारत तथा चीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। चीन द्वारा निर्मित पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस बढ़ती आर्थिक सक्रियता का उदाहरण है। भारत को नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हुए यह समझना होगा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध भरोसे और सहयोग से मजबूत होते हैं। नेपाल को भी अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के बीच भारत के साथ ऐतिहासिक निकटता और पारस्परिक हितों को संतुलित रखना होगा। हवाई संपर्क का प्रश्न भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। नेपाल लंबे समय से अपने भैरहवा और पोखरा हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों की मांग करता रहा है। यात्रा के दौरान काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ के मौजूदा हवाई मार्ग को दोतरफा बनाने पर सहमति बनी है लेकिन अन्य प्रस्तावों पर तकनीकी बातचीत जारी रहेगी। सुरक्षा संबंधी भारतीय चिंताओं और नेपाल की आर्थिक आवश्यकताओं के बीच व्यवहारिक संतुलन बनाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों का अंतर समाप्त होना चाहिए। अतीत में अनेक परियोजनाओं की घोषणा हुई लेकिन भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय बाधाओं और राजनीतिक मतभेदों के कारण वे समय पर पूरी नहीं हो सकीं। इस यात्रा में गठित उच्चस्तरीय निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाकर प्रत्येक छह महीने में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। सीमा विवाद पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता आगे बढ़नी चाहिए और प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह की अप्रकाशित रिपोर्ट पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। भारत के लिए नेपाल केवल एक छोटा पड़ोसी देश नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। वहीं, नेपाल को भी यह समझना होगा कि भारत के साथ स्थिर और विश्वसनीय संबंध उसकी आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ संबंधों की गुणवत्ता अवश्य बदली जा सकती है। बालेन्द्र शाह की पहली भारत यात्रा ने संबंध सुधारने का अवसर उपलब्ध कराया है लेकिन इसे ऐतिहासिक सफलता तभी कहा जा सकेगा जब सीमा विवाद पर सार्थक प्रगति हो, 1950 की संधि की समीक्षा सम्मानजनक तरीके से पूरी हो और विकास परियोजनाएं जमीन पर दिखाई दें। कूटनीति का मूल्य संयुक्त घोषणापत्रों की लंबाई से नहीं बल्कि जनता के जीवन में आए बदलाव से तय होता है। भारत और नेपाल को संदेह की राजनीति से निकलकर साझेदारी की राजनीति अपनानी होगी। हिमालय की ऊंचाइयों की तरह दोनों देशों की मित्रता भी तभी स्थायी होगी, जब उसकी नींव विश्वास, समानता और पारस्परिक सम्मान पर टिकी होगी।

यदि हम चुनावी गणित और जमीनी हकीकत का सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो दोनों ही पहलू एक-दूसरे में गुंथे हुए नजर आते हैं। अकाली दल के लिए यह अस्तित्व का संकट है। पंथिक राजनीति का स्वयंभू ध्वजवाहक होने के बावजूद, पार्टी अपने ही गढ़ में सिमटती चली गई और उसका नेतृत्व विश्वसनीयता के संकट से जूझता रहा। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती अलग किस्म की है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रचंड बहुमत और संगठनात्मक विस्तार के बावजूद, पंजाब के ग्रामीण अंचलों में भाजपा अपनी पैठ बनाने में विफल रही। लोकसभा चुनावों में पार्टी के मत प्रतिशत में भले ही उछाल आया हो, लेकिन सीटों के खाते में शून्य दर्ज होना इस बात का प्रमाण था कि शहरी हिंदू मतदाताओं के भरोसे पंजाब की सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्पष्ट है कि एक के पास ग्रामीण सिख आधार है जो बिखर चुका है, तो दूसरे के पास शहरी जनाधार है जो सत्ता के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में एक-दूसरे का हाथ थामना दोनों के लिए एक ऐसी व्यावहारिक मजबूरी बन गया, जिसे अब पंजाब के कल्याण और जरूरत के आवरण में लपेटकर पेश किया जा रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पंजाब एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सीमा पार से होने वाली नशे की तस्करी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, विदेश पलायन की होड़ और कानून-व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को भीतर से खोखला किया है।

विचार

पंजाब में सियासी समीकरणों की नई करवट

अशोक भाटिया



भारतीय राजनीति के क्षितिज पर चौबीस नवंबर की तारीख एक ऐसे पुनर्मिलन की साक्षी बनी है, जिसकी आहट पिछले कई महीनों से सुनाई दे रही थी। छह वर्ष के लंबे अलगाव के बाद शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर हाथ मिला लिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में हुआ यह ऐलान महज दो राजनीतिक दलों का चुनावी समझौता भर नहीं है। यह समकालीन भारतीय राजनीति के उस जटिल दौर की बानगी है, जहां विचारधारा की कठोरता से अधिक प्रासंगिक बने रहने की जिद और सामाजिक समीकरणों को साधने की बाध्यता हावी दिखाई देती है। आज जब उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय विमर्श के बीच नया संतुलन तलाशा जा रहा है, तब पंजाब के इस घटनाक्रम को केवल एक सीमावर्ती राज्य की चुनावी बिसात मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके निहितार्थ कहीं अधिक गहरे, सामाजिक और राष्ट्रीय हैं। इस गठबंधन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा, जो सन उन्नीस सौ छियानवे में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल की दूरदर्शिता से लिखे गए थे। करीब ढाई दशकों तक यह गठबंधन पंजाब में केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद के काले साये से बाहर निकले राज्य में हिंदू और सिख समुदायों के बीच विश्वास का एक मजबूत सेतु भी बना। लेकिन वर्ष दो हजार बीस में तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर उपजे तीव्र किसान आंदोलन ने इस ऐतिहासिक साझेदारी की नींव हिला दी। अकाली दल ने अपने पारंपरिक ग्रामीण और किसान वोट बैंक को बचाने के लिए राजग से नाता तोड़ लिया। उस समय यह कदम अकाली नेतृत्व को राजनीतिक रूप से सुरक्षित लगा था, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि अलग-अलग राहें चुनना दोनों ही दलों के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। वर्ष दो हजार बाईस के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों ने दोनों दलों को यह कड़वा सच दिखा दिया कि पंजाब की बहुकोणीय राजनीति में अकेले चलकर वे हाशिये पर धकेले जा रहे हैं। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह पुनर्मिलन दोनों दलों की राजनीतिक जरूरत है या फिर अस्तित्व बचाने की मजबूरी।

यदि हम चुनावी गणित और जमीनी हकीकत का सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो दोनों ही पहलू एक-दूसरे में गुंथे हुए नजर आते हैं। अकाली दल के लिए यह अस्तित्व का संकट है। पंथिक राजनीति का स्वयंभू ध्वजवाहक होने के बावजूद, पार्टी अपने ही गढ़ में सिमटती चली गई और उसका नेतृत्व विश्वसनीयता के संकट से जूझता रहा। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती अलग किस्म की है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रचंड बहुमत और संगठनात्मक विस्तार के बावजूद, पंजाब के ग्रामीण अंचलों में भाजपा अपनी पैठ बनाने में विफल रही। लोकसभा चुनावों में पार्टी के मत प्रतिशत में भले ही उछाल आया हो, लेकिन सीटों के खाते में शून्य दर्ज होना इस बात का प्रमाण था कि शहरी हिंदू मतदाताओं के भरोसे पंजाब की सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्पष्ट है कि एक के पास ग्रामीण सिख आधार है जो बिखर चुका है, तो दूसरे के पास शहरी जनाधार है जो सत्ता के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में एक-दूसरे का हाथ थामना दोनों के लिए एक ऐसी व्यावहारिक मजबूरी बन गया, जिसे अब पंजाब के कल्याण और जरूरत के आवरण में लपेटकर पेश किया जा रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पंजाब एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सीमा पार से होने वाली नशे की तस्करी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, विदेश पलायन की होड़ और कानून-व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को भीतर से खोखला किया है। नशाखोरी के खिलाफ दिसंबर दो हजार उनतीस तक की समय-सीमा तय करना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इसका समाधान किसी एक दल की चुनावी घोषणा से संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, पंजाब के समाज में शहरी और ग्रामीण विभाजन की जो खाई पिछले कुछ वर्षों में चौड़ी हुई है, उसे पाटना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गठबंधन के ऐलान के वक्त दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने इसे हिंदू-सिख एकता और सद्भाव का प्रतीक बताया है।

यदि यह गठबंधन वास्तव में सामाजिक ध्रुवीकरण को रोकने और दोनों समुदायों के बीच संवाद बहाल करने का माध्यम बनता है, तो यह पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए शुभ संकेत होगा। इस घटनाक्रम का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के दक्षिणी राज्यों से लेकर पूर्वी और पश्चिमी छोर तक, आज भारतीय राजनीति में गठबंधन धर्म की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। एक दौर था जब यह माना जाने लगा था कि राष्ट्रीय दलों के उभार के साथ क्षेत्रीय दलों का महत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन समय का चक्र देखिए कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल को भी विभिन्न राज्यों में स्थानीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों की आवश्यकता महसूस हो रही है। पंजाब में भाजपा द्वारा अकाली दल को बड़े भाई की भूमिका देना और मुख्यमंत्री पद पर उसका दावा स्वीकार करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संघीय ढांचे में क्षेत्रीय अस्मिता की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह संदेश दक्षिण भारत के उन राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय दलों पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसी विविधता और शक्ति संतुलन में निहित है, जहां केंद्र और राज्य की आकांक्षाएं एक-दूसरे की पूरक बनकर चलें। तमाम सियासी गुणा-भाग के बावजूद, इस गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं है, जितनी मंच से दिखाई दे रही है। राजनीति में दो और दो हमेशा चार नहीं होते। छह साल पहले जिन किसानों के गुस्से के कारण यह गठबंधन टूटा था, उनके मन में आज भी कई आशंकाएं जीवित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि सुधारों से जुड़े मुद्दे अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इस बात पर संदेह जता रहा है कि क्या दोनों दलों का पारंपरिक वोट बैंक एक-दूसरे को आसानी से स्थानांतरित हो पाएगा। ग्रामीण सिख मतदाता अकाली दल के इस कदम को किस रूप में लेगा और क्या वह फिर से उस नेतृत्व पर भरोसा कर पाएगा जिस पर अवसरवादिता के आरोप लग रहे हैं, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरी तरफ, भाजपा के भीतर भी वह कार्यकर्ता जो पिछले छह वर्षों से अकेले दम पर पार्टी को खड़ा करने का सपना देख रहा था, सीटों के नए बंटवारे में खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकता है।

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस नए समीकरण को अवसरवादी गठजोड़ करार देकर हमलावर हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों पर बादल परिवार के पुराने रुख और अंतरराज्यीय जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति बेहद तीखी और भावनात्मक होने वाली है। ऐसे में अकाली-भाजपा गठबंधन के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के बीच के अविश्वास को मिटाकर एक साझा जमीनी अभियान खड़ा करना होगा। दूसरी, उन्हें पंजाब की जनता के सामने विकास, रोजगार, कृषि संकट और नशा मुक्ति का एक ऐसा ठोस खाका रखना होगा जो केवल चुनावी वादा न लगे, बल्कि जिसमें एक विजन दिखाई दे। दरअसल , लोकतंत्र में किसी भी गठबंधन की सार्थकता इस बात से तय नहीं होती कि उसने सत्ता के कितने सोपान चढ़े, बल्कि इस बात से होती है कि उसने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव लाया। पंजाब देश का अन्नदाता और सीमाओं का सजग प्रहरी है। जब पंजाब अस्थिर होता है या आर्थिक-सामाजिक संकट से घिरता है, तो उसकी टीस पूरे राष्ट्र को महसूस होती है।

'वंदे मातरम्' पर तौबा करने वाले मजहबी ठेकेदारों से सवाल- मातृभूमि से ऊपर मजहब कैसे?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

श्रीनगर में वक्फ बोर्ड के एक सरकारी समारोह में 'वंदे मातरम्' बजा। उपस्थित इमामों और उलेमाओं में से कुछ सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े हुए। इसके बाद जब इस घटना के वीडियो सामने आए तो कुछ मजहबी प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और तौबा करने के साथ कलमा पढ़कर अपने ईमान की पुष्टि करने की बात कही। यह घटनाक्रम अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर हुआ क्या था? उन्होंने किसी की धार्मिक उपासना की थी या अपने देश के राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े हुए थे? क्या अपनी जन्मभूमि के प्रति सम्मान प्रकट करना भी अब ईमान के लिए खतरा बन गया है? जरा उन लोगों से पूछिए, जिन्होंने इन मजहबी (धर्मगुरुओं) को अपने इस आचरण के लिए माफी मांगने पर विवश किया, क्या भारत उनकी मातृभूमि नहीं है? क्या वे इस देश की मिट्टी में जन्मे नहीं हैं? क्या इसी देश का अन्न खाकर उनका शरीर नहीं बना? क्या इसी देश की हवा में सांस लेकर उनका जीवन आगे नहीं बढ़ा? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह उपजता है कि क्या मृत्यु के बाद उनका शरीर भी इसी धरती में नहीं मिल जाएगा? फिर इतना जानने-समझने के बाद भी इस मातृभूमि के सम्मान में खड़े होने पर इतना संकट क्यों? क्या किसी राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति ने अपनी धार्मिक मान्यता बदल ली? वास्तव में यह उस मानसिकता पर सवाल है जो कथित इस्लाम की संकीर्ण व्याख्या के सहारे राष्ट्रीय सम्मान और मजहबी आस्था को आमने-सामने खड़ा करने का प्रयास करती है।'वंदे मातरम्' को लेकर आपत्ति करने वालों को सबसे पहले इसके भाव और संदर्भ को समझना चाहिए। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की इस कालजयी रचना के शुरुआती दो छंदों में मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता, उसके जल, फल, हरियाली और शीतल हवाओं का वर्णन है। जिस देवी स्वरूप का वर्णन है, वह भी उनके हाथ, पैर ज्ञान, विज्ञान हम सभी से निर्मित लोक है। वस्तुत: यह उस धरती के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव है, जिसने मनुष्य को जीवन दिया है। निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए, पर उसके नाम पर मातृभूमि के प्रति सम्मान जताने वालों को अपराधबोध से भरना कहां तक उचित है? नहीं। किसी व्यक्ति का राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़ा होना और उसके लिए बाद में उसे तौबा करने पर विवश किया जाना दो अलग-अलग विषय हैं।

इस्लाम की चर्चा करने वाले मजहबी उलेमाओं को यह भी याद रखना चाहिए कि मातृभूमि से प्रेम की भावना इस्लामी परंपरा से अपरिचित नहीं है। 'हुब्बुल वतन' अर्थात वतन से प्रेम की अवधारणा मुस्लिम समाज में लंबे समय से प्रचलित है। 'हुब्बुल वतन मिनल ईमान' पैगंबर मोहम्मद की प्रमाणित हदीस भले ही न हो, किंतु इसे एक प्रसिद्ध सूक्ति माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत करने के प्रसंग में अपनी जन्मभूमि मक्का के प्रति उनके लगाव का उल्लेख मिलता है। फिर भारत में जन्म लेने वाले मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने और उसके सम्मान में खड़े होने में कैसी परेशानी होनी चाहिए? क्या भारत उनके लिए अपना देश नहीं है? क्या इस देश की सुरक्षा, समृद्धि और प्रतिष्ठा में उनका कोई दायित्व नहीं है? क्या उनकी संतानों का भविष्य इसी देश से नहीं जुड़ा है? इस्लाम के नाम पर मातृभूमि के सम्मान को संदेह के घेरे में खड़ा करने वालों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने भारत की स्वाधीनता के लिए फांसी का फंदा चूमा। उनके लिए देश की स्वतंत्रता किसी मजहबी पहचान से अधिक मातृभूमि के स्वाभिमान का प्रश्न थी। अनेक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। क्या आज उनकी विरासत को भूलकर इस्लामिक मजहबी संकीर्णता को बढ़ावा देना उचित है? इस श्रीनगर की घटना का सबसे विचारणीय पक्ष यही है कि कुछ मजहबी उलैमा, मौलवी पहले राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े हुए और उसके बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तथा तौबा करने लगे। मौलाना फारूक सहित कुछ उलेमाओं ने तो वीडियो संदेश में अपनी कार्रवाई पर प्रायश्चित की बात कही और कलमा पढ़ने का उल्लेख किया। दूसरी ओर, मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में गीत बजाए जाने पर आपत्ति जताई और इसे तौहीद के सिद्धांत से जोड़कर देखा। क्या इन मजहबी मौलवीयों को यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी कही गई बात का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि वे अपनी इस्लामिक व्याख्या के माध्यम से लोगों में यह धारणा पैदा करेंगे कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़ा होना भी गुनाह है, तो इससे धार्मिक समुदाय और राष्ट्रीय समाज के बीच अनावश्यक दूरी बढ़ेगी।

एक नजर

सोनपुर मेले में पशुपालन विभाग के मुख्य पंडाल का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय अपर सचिव ने लिया चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा

सारण। बिहार में सारण जिले के सोनपुर में विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला में पशुपालकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में जिला पशुपालन मुख्य पंडाल का उद्घाटन सारण क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ कांता प्रसाद ने किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के डेयरी एवं पशुपालन विभाग के अपर सचिव रामाशंकर सिन्हा मुख्य रूप से पहुंचे। अपर सचिव रामाशंकर सिन्हा ने निदेशालय पटना के डॉ दिनेश कुमार जौनपुरी और वैशाली के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ रविशंकर विद्यार्थी के साथ मेला परिसर में संचालित अस्थायी पशु चिकित्सा शिविरों, घोड़ा वार्ड एवं बकरी वार्ड का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण और उपलब्ध कराई जा रही उपचार सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की।

उद्घाटन समारोह में सारण के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार दास, डॉ. हिमांशु, डॉ. दिलीप झा, डॉ. शिवशंकर एवं डॉ. संतोष कुमार सहित कई विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मेले में कुल 1,113 घोड़े पहुंचे हैं, जिनमें से अब तक 194 घोड़ों की बिक्री हो चुकी है। घोड़ों की अधिकतम कीमत 1,80,000 रुपये और न्यूनतम 25,000 रुपये दर्ज की गई है। इसके अलावा मेले में 216 बकरी-भेड़ कुल 91 की बिक्री, अधिकतम कीमत 24,000 रुपये, 115 कुत्ते, 12 फ्रिजियन, 02 गिर, 01 साहिवाल, 04 भैंस और 06 देशी बछौर बैल 04 की बिक्री मौजूद हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार मेला परिसर और सोनपुर स्थित पशु चिकित्सा शिविर में अब तक कुल 108 बीमार पशुओं का उपचार किया जा चुका है। पशुपालन विभाग की समुचित व्यवस्थाओं के कारण सोनपुर का यह ऐतिहासिक पशु मेला अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

एचआईवी नियंत्रण में सीवान ने रचा इतिहास, 95-95-95 का लक्ष्य हासिल करने वाले 23 जिलों में शामिल

सीवान। एचआईवी संक्रमण पर नियंत्रण की दिशा में सीवान जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के निर्धारित 95-95-95 लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बिहार के 23 जिलों में सीवान भी शामिल हो गया है। जिले ने पहले चरण में 95 प्रतिशत, दूसरे चरण में 98 प्रतिशत और तीसरे चरण में भी 98 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। इस सफलता के साथ सीवान एचआईवी नियंत्रण के मामले में राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 6,436 है। इनमें से 6,138 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। वहीं, करीब 6,006 मरीज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) के तहत नियमित उपचार प्राप्त कर रहे हैं। उपचार करा रहे मरीजों में वायरल लोड की जांच और नियमित निगरानी के माध्यम से संक्रमण को नियंत्रित रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। 95-95-95 रणनीति का उद्देश्य एचआईवी संक्रमित 95 प्रतिशत लोगों की पहचान करना, पहचान किए गए लोगों में से 95 प्रतिशत को उपचार से जोड़ना और उपचाररत 95 प्रतिशत मरीजों में वायरल लोड को दबाकर संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करना है। बिहार में एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम के प्रदर्शन के आधार पर जिलों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। इनमें 23 जिले सुरक्षित, 13 जिले सक्षम और दो जिले संघर्षशील श्रेणी में शामिल हैं। सीवान का सुरक्षित श्रेणी में पहुंचना जिले में एचआईवी जांच, संक्रमितों की पहचान, उपचार और फॉलोअप की व्यवस्था में हुए सुधार को दर्शाता है। सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में सीवान की यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए गर्व की बात है।

संविधान देश की आत्मा, नियमों का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति : अभिनंदन सिंह

भागलपुर। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर, भागलपुर में गुरुवार को छात्रों एवं आचार्यों द्वारा पूरे उत्साह के साथ 'संविधान दिवस' मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान के मूल्यों के स्मरण के साथ हुई। इस अवसर पर विद्यालय के उपप्रधानाचार्य अभिनंदन सिंह ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है, जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीने का अवसर प्रदान करता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक नियमों का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवधेश कुमार भारती ने कहा कि नागरिकों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व भाव तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की समझ संविधान से ही विकसित होती है। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें जानकर अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना ही संविधान दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता है। वहीं, रतन पाठक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का बोध कराने वाला हमारा संविधान समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। समारोह के दौरान विद्यालय के कैडेट पियूष गुप्ता, दिव्यांशु कुमार, आदर्श कुमार, यशस्वी राज, सत्यम कुमार एवं आरव कुमार ने भी संविधान दिवस के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। पूरे कार्यक्रम का सफल मंच संचालन कैडेट यशस्वी राज द्वारा किया गया। इस मौके पर शांतनु आनंद, मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा, चंद्रचूड़ कुमार, चंदन पांडे सहित विद्यालय के सभी आचार्य बंधु-भगिनी एवं छात्र उपस्थित रहे।

राजीव गांधी की सुरक्षा हटाने के दावे पर भड़की भाजपा, प्रीति शेखर ने कांग्रेस को ही घेरा

भागलपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अपने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से पूर्व उनकी सुरक्षा जानबूझकर हटाए जाने संबंधी दावे के बाद देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भागलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा बिहार की प्रदेश महामंत्री सह प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इस पूरे मामले में कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा किया। प्रीति शेखर ने कहा कि जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपनी ही पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व से जवाब मांगना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हर पहलू का जवाब कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व और सरकार को देना चाहिए। राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देने से पहले तथ्यों को जनता के सामने रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता भी यह जानने का हक रखती है कि आखिर उस समय राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए थे और उसके पीछे क्या ठोस कारण थे। प्रीति शेखर ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या देश के इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना है। इस गंभीर विषय से जुड़े सवालों पर सस्ती राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब सामने आने चाहिए, ताकि देश के सामने सच्चाई स्पष्ट हो सके।

संविधान भारत की एकता, अखंडता, न्याय और लोकतांत्रिक चेतना का आधार: संजय सरावगी

पटना,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं दरभंगा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि संविधान भारत की एकता, अखंडता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक चेतना का आधार है। हमारा संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के आदर्शों और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। संविधान गौरव दिवस के अवसर पर गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संविधान निर्माताओं, विशेषकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया।



इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण, पद्मश्री डॉ. आर.एन. सिंह, न्यायमूर्ति हेमंत शरण, भाजपा की बिहार सह-प्रभारी संगीता यादव, ब्रह्माकुमारी संगीता बहन, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सरावगी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। यह दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर संविधान को किताबों की अलमारियों से निकालकर देश के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारों और उनके सपनों को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज जो कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है, उसी ने अपने शासनकाल में अनुच्छेद 356 का बार-बार दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। वर्ष 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान प्रेम सत्ता से बाहर होने पर ही जागता है। संविधान की रक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले अपने इतिहास का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और उसकी आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। असहमति लोकतंत्र का आभूषण है, लेकिन असंवैधानिकता लोकतंत्र का अपमान है। संविधान के प्रति सम्मान किसी फैसले की अनुकूलता के आधार पर नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखने से प्रदर्शित होता है। सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश में एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर कानून के शासन को मजबूत करने का काम हुआ है। उन्होंने उपस्थित लोगों से संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी को संविधान गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

57वें आईएफएफआई के पांचवें दिन बिहार पवेलियन में उमड़े फिल्मकार, फिल्म नीति और अनुदान प्रक्रिया की ली जानकारी

गोवा। गोवा में संपन्न 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) के पांचवें दिन बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के पवेलियन में फिल्म जगत के लोगों ने फिल्म नीति की जानकारी प्राप्त की। फिल्म निगम के परामर्शी (फिल्म) प्रो अरविंद रंजन दास ने पवेलियन आए लोगों को फिल्म नीति, शूटिंग की अनुमति और अनुदान की प्रक्रिया को समझाया।

बिहार पवेलियन पहुंचे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार का अनुभव सागर सहित बिहार फिल्म निगम की टीम ने स्वागत किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अभिनेता पंकज झा का अभिनंदन किया। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) के अधिकारियों ने बिहार फिल्म निगम के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने की प्रतिबद्धता जताई। पंकज झा ने कहा कि बिहार में हर तरह की फिल्में शूट हो सकती हैं। बिहार के सिनेमैटिक लोकेशन की वजह से फिल्मकार हमेशा से यहां शूट करते रहे हैं, यह जरूर है कि अनुदान मिलने की वजह से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी स्कीम से आर्ट और नन-कमर्शियल फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा और भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाओं में मानवीय मूल्य स्थापित करने वाली फिल्में बनेंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म नीति की सब्सिडी स्कीम से फिल्मकारों को फिल्म निर्माण में प्रयोग करने की हिम्मत मिलेगी और वे नए विषयों पर लीक से हटकर फिल्में बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कोशिश होनी चाहिए कि फिल्में दु:ख और तकलीफ को भूलने भर का ही माध्यम बनकर नहीं रह जाए, बल्कि मानव जागृति का मजबूत स्तंभ बने। फिल्म निगम के आमंत्रण पर बिहार पवेलियन पहुंचे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता कामाख्या नारायण सिंह को संचार सलाहकार कुमार गौरव ने आईएफएफआई में उनकी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड' चयन के लिए बधाई दी और सम्मानित किया। वह फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं। इस फिल्म को आईएफएफआई के इंडियन पैनोरमा खंड में चुना गया है। यह फिल्म महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। सनशाइन के बैनर तले विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा, अदिति भाटिया, सुमित गहलावत और अर्जन औजला प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए बिहार खनिज नियमावली में संशोधन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति

पटना। बिहार में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने तथा खनिज राजस्व की सुरक्षा के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधित नियमावली में खनिजों के ग्रेड का गलत वर्गीकरण रोकने, परिवहन वाहनों का निबंधन एवं डिजिटल डाटाबेस तैयार करने, जीपीएस निगरानी अनिवार्य करने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा की अवैध निकासी को सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी जरूरी उपायों के जरिए इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।सरकार तकनीक आधारित निगरानी एवं कठोर प्रवर्तन के माध्यम से अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य खनिज संसाधनों का पारदर्शी उपयोग, राजस्व की सुरक्षा और बिहार के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। लौह अयस्क का सही वर्गीकरण: गलत ग्रेड निर्धारण से होने वाली राजस्व क्षति रोकने के लिए नियम-17 में नया प्रावधान। उत्तराधिकारियों को राहत: खनिज समानुदानधारी अथवा लेटर ऑफ इन्टेन्ट धारक की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण की सुविधा।

प्रबंधन शुल्क: पीला बालू पर 20 रुपये, उजला बालू पर 10 रुपये और पत्थर पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क। इससे प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व का अनुमान। वाहनों का निबंधन एवं जीपीएस: लघु खनिज परिवहन वाहनों का निबंधन तथा अन्य राज्यों से खनिज लेकर बिहार आने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। दंड का प्रावधान: जीपीएस नहीं लगाने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं हाफ ट्रक पर 50,000 रुपये तथा बड़े वाहनों पर 2 लाख रुपये का दंड। अवैध परिवहन पर कार्रवाई: संपूर्ण खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क जमा होने तक संबंधित वाहनों के लिए खनिज चालान जारी नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इन संशोधनों से अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, खनिज राजस्व सुरक्षित रहेगा और खनन व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।

कांग्रेस की 'संविधान बचाओ यात्रा' लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक दिखावा और खोखली नौटंकी: प्रेम रंजन पटेल

पटना,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस की तथाकथित 'संविधान बचाओ यात्रा' राजनीतिक पाखंड, जनता को भ्रमित करने की कोशिश और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का एक और अवसरवादी अभियान मात्र है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बार-बार संविधान की मर्यादाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की धज्जियाँ उड़ाई, आज वही कांग्रेस संविधान बचाने का ढोंग कर रही है। यह देश की जनता के साथ राजनीतिक छलावा है।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान बचाने की बात करने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास और संविधान के साथ किए गए व्यवहार का जवाब देश की जनता को देना चाहिए। आपातकाल लगाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलना, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और लोकतंत्र की आवाज को दबाना क्या यही कांग्रेस का संविधान बचाने का मॉडल था। कांग्रेस का इतिहास संविधान की दुहाई देने का नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार में संविधान की मर्यादाओं को ताक पर रखने का इतिहास रहा है। संविधान किसी राजनीतिक परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, न ही सत्ता प्राप्ति और सत्ता बनाए रखने का कोई राजनीतिक औजार। कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता को परिवार केंद्रित राजनीति, वंशवाद और निजी हितों के लिए केवल इस्तेमाल किया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति लंबे समय तक एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही। आज जब देश लोकतांत्रिक चेतना, पारदर्शिता और जवाबदेही के नए दौर में आगे बढ़ रहा है, तब कांग्रेस संविधान की आड़ लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि संविधान केवल मंचों पर भाषण देने, यात्राएं निकालने, नारे लगाने और राजनीतिक फोटो खिंचवाने का विषय नहीं है। संविधान का सम्मान व्यवहार में दिखना चाहिए, शासन में दिखना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी में दिखना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में दिखना चाहिए। संविधान को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसी संविधान की रक्षा का ढोल पीटना कांग्रेस की दोहरी राजनीति को उजागर करता है। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जनता कांग्रेस के राजनीतिक छल, झूठे झलावे और भ्रम फैलाने की राजनीति को भली-भांति समझती है। कांग्रेस जितनी बार संविधान बचाओ का नारा लगाएगी, जनता उतनी ही बार उसके अतीत, आपातकाल और सत्ता के दुरुपयोग के इतिहास को याद करेगी। देश अब किसी राजनीतिक दल के बहकावे, झांसे और भावनात्मक नारों में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों, गरीबों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को मजबूती देने का संकल्प लिया जा चुका है।

बिहार: उद्योगों की चिमनियां अब लिख रही है उम्मीद की नई कहानी

पटना,एजेंसी। बिहार में त्योहारों के बाद रेलवे स्टेशनों पर बैग लेकर खड़े युवाओं की भीड़ और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर उनका पलायन लंबे समय से राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में रहा है। अब इस तस्वीर को बदलने की दिशा में ठोस पहल हो रही है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में औद्योगिक विकास की कोशिशें अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं। कंपनियां निवेश कर रही हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं और रोजगार के हजारों अवसर तैयार होने की उम्मीद है। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में 40 बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। इनमें कुल करीब 21,600 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इन इकाइयों से लगभग 23,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इसके अलावा, बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर भी 19 बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं या पहले से संचालित हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों का यह विस्तार कुल 17 जिलों तक पहुंच चुका है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, बक्सर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, बांका, अररिया, वैशाली, पश्चिम चंपारण और कैमूर शामिल हैं।



बिहार में देश के कई जाने-माने औद्योगिक समूह भी निवेश कर रहे हैं। सीमेंट क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट की नवादा और मुजफ्फरपुर, अल्ट्राटेक की बांका और भागलपुर तथा जेके लक्ष्मी सीमेंट की मधुबनी में परियोजनाएं शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भागलपुर के पीरपैंती में अदाणी पावर का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण चरण में करीब 8,100 और संचालन शुरू होने के बाद लगभग 2,300 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसी तरह, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हल्दीराम, मदर डेयरी, आईटीसी, वरुण बेवरेजेस और अमूल से जुड़ी कैरा मिल्क यूनियन की परियोजनाएं शामिल हैं। पेट्रोलियम और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम का हथुआ में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, मधुबनी में रिलायंस की बायोगैस परियोजना और एचपीसीएल रिन्यूएबल की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तकनीकी क्षेत्र में पटना में सीटीआर एलएस और भारती एयरटेल के डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, प्लास्टिक और पाइप उद्योग में सुप्रीम इंडस्ट्रीज तथा प्रिंस पाइप्स जैसी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं।

खेत से फैक्ट्री तक बढ़ रहा उद्योगों का दायरा

बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसान हैं। राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं के तहत कृषि उत्पादन को उद्योगों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में अकेले इस क्षेत्र की 13 इकाइयां हैं। खगड़िया में मक्का क्लस्टर और स्टार्च उत्पादन, अररिया में आटा, मैदा और मखाना मिल, मुंगेर में डेयरी प्लांट तथा पटना और बिहटा में नमकीन, बिस्कुट और पेय पदार्थों से जुड़ी इकाइयां इसके उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही बाजार उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इथेनॉल और बायोगैस के क्षेत्र में भी बिहार में कई परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय और गोपालगंज में इथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) की परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे कृषि अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकेगा। इससे एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों की अतिरिक्त आमदनी के रास्ते भी खुल सकते हैं।

सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार में औद्योगिक विकास की तैयारी

राज्य में औद्योगिक विकास को किसी एक शहर तक सीमित रखने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए बिहार को नौ औद्योगिक क्लस्टरों में बांटा गया है। इनमें पटना, बिहटा, हाजीपुर, मोतीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया, गया और भागलपुर शामिल हैं। इसका उद्देश्य मिथिलांचल, कोसी-सीमांचल, मगध और भोजपुर सहित राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ताकि युवाओं को अपने गृह जिले या आसपास के क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर मिल सकें। इन क्लस्टरों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट और बिजली से लेकर टेक्सटाइल, सोलर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोसेंसर और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी परियोजनाएं शामिल हैं। पंडौल में टेक्सटाइल, बरियारपुर में सोलर मॉड्यूल, सिकंदरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोसेंसर तथा भागलपुर और हाजीपुर में लॉजिस्टिक्स पार्क की योजनाएं हैं। इसके अलावा मधुबनी में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पार्क भी प्रस्तावित है।

सरकार की पहल और जमीन पर उतरती परियोजनाएं

किसी भी कंपनी के लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश बड़ा फैसला होता है। इसके लिए जमीन, बिजली, सड़क और स्थिर औद्योगिक नीतियों जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भरोसा जरूरी है। बिहार में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने के पीछे भी इन सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास अहम हैं। भूमि आवंटन के बाद कई औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं, कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ इकाइयों को जमीन आवंटित की जा चुकी है और वे अगले चरण की तैयारी में हैं। इस तरह राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार लगातार आगे बढ़ रहा है।

एक नजर

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए डिएंड्रा डॉटिन की वेस्टइंडीज टीम में वापसी



नई दिल्ली। वेस्टइंडीज की अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन पाकिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों की टीम में लौट आई हैं। वेस्टइंडीज को इस सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने हैं। डॉटिन सितंबर में जिम्बाब्वे दौरे पर वेस्टइंडीज के पिछले अंतरराष्ट्रीय अभियान का हिस्सा नहीं थीं। उन्हें निजी कारणों से अवकाश दिया गया था। डॉटिन को चोट के कारण सीरीज से बाहर हुई ऑफ स्पिनर अशमिनी मुनिसार की जगह टीम में शामिल किया गया है। बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज ने दोनों प्रारूपों के लिए एक ही 15 सदस्यीय टीम चुनी है। हेली मैथ्यूज टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि चिनेल हेनरी उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी। इस सीरीज के साथ मैथ्यूज की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी वापसी होगी। जिम्बाब्वे दौरे के टी20 चरण के लिए उन्हें निजी कारणों से अवकाश दिया गया था। उनकी गैरमौजूदगी में हेनरी ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दिलाई थी। इससे पहले टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज ने 2028 के संस्करण के लिए पहले ही अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मुकाबले आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। यह चैंपियनशिप 2029 के वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों का निर्धारण करती है। तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले 8, 10 और 12 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 15, 17 और 20 दिसंबर को वनडे मुकाबले होंगे। सीरीज के सभी मैच डोमिनिका के रोसेउ स्थित विंडसर पार्क में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान सीरीज के लिए वेस्टइंडीज महिला टीम:

हेली मैथ्यूज (कप्तान), चिनेल हेनरी (उपकप्तान), आलिया एलीन, एबोनी ब्रैथवेट, शेमेन कैंपबेल, जहजारा क्लैक्सटन, डिएंड्रा डॉटिन, अफी फ्लेचर, जैनिलिया ग्लासगो, रियालियाना ग्रिमंड, शॉनिशा हेक्टर, जैडा जेम्स, मैंडी मंगरू, करिश्मा रामहरैक और स्टेफनी टेलर।

एसए20: डरबन सुपर जायंट्स के नए मुख्य कोच बने केन विलियमसन



जोहानसबर्ग। डरबन सुपर जायंट्स ने एसए20 के पांचवें सत्र के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। विलियमसन इससे पहले एसए20 के तीसरे और चौथे सत्र में खिलाड़ी के रूप में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब वह कोच की भूमिका में किंग्समीड लौटेंगे। वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी लांस क्लूजनर की जगह लेंगे। क्लूजनर लीग की शुरुआत से ही पिछले चार सत्रों से डरबन की टीम के मुख्य कोच रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में टीम ने दूसरे सत्र में उपविजेता रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 36 वर्षीय विलियमसन को शुरुआत में पांचवें सत्र के लिए डरबन सुपर जायंट्स की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें कोच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। अपनी पीढ़ी के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाने वाले विलियमसन के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का व्यापक अनुभव है। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। इस टूर्नामेंट में विलियमसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। इसके बाद उन्होंने 2021 में पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड को खिताबी जीत दिलाई थी। इस नियुक्ति के साथ आरपी-संजीव गोयनका समूह के साथ विलियमसन का जुड़ाव और मजबूत हुआ है। अक्टूबर 2025 में वह 2026 आईपीएल सत्र से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के रणनीतिक सलाहकार बने थे। इसके अलावा वह द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के पुरुष बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। एडेन मार्करम एक बार फिर डरबन सुपर जायंट्स की कप्तानी करेंगे। उन्होंने पिछले सत्र में पहली बार टीम का नेतृत्व किया था।

शतरंज के महाकुंभ में अर्जुन अवार्डी, कॉमनवेल्थ विजेता, एशियाई चैंपियन होंगे शामिल

वाराणसी। वाराणसी में पहली बार आयोजित 63 वें सेठ एमआर जैपुरिया राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप में इस बार 20 से अधिक ग्रैंड मास्टर, 20 इंटरनेशनल मास्टर, 15 कैंडिडेट मास्टर के अलावा 24 फिडे मास्टर हिस्सा लेंगे। इनके साथ ही 115 ऐसे खिलाड़ी है, जो फिडे टाइटल और फिडे एरिना टाइटल धारक है। इसमें अर्जुन अवार्डी, कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशियाड चैंपियन और शतरंज ओलंपियाड विजेता भी शामिल हो रहे हैं। बाबतपुर स्थित सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल के प्रांगण में 29 से 9 दिसंबर तक होने वाली इस चैंपियनशिप में अभी तक 321 प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा संस्थागत दल भी शामिल होंगे। वाराणसी चेस एसोसिएशन एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक बजाज ने बताया कि चैंपियनशिप में गत बार के राष्ट्रीय चैंपियन जीएम सीड 1 पी. इनियान चेस की बाजी खेलते दिखेंगे। उनके साथ ही छः बार के विजेता, अर्जुन अवार्डी, पूर्व एशियाड चैंपियन जीएम सीड 3 सूर्य शेखर गांगुली भी इस बार दिमागी कसरत करते दिखेंगे। गांगुली शतरंज के बादशाह कहे जाने वाले विश्वनाथन आनंद की विश्व चैंपियनशिप विजेता टीम के प्रमुख सहयोगी रहे हैं।

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी: मलेशिया की चुनौती से पार पाना चाहेगा भारत



भोपाल। गत चैंपियन और विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार को मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 के सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगी। नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम लगातार पांच जीत के साथ लीग चरण में शीर्ष पर रहने के बाद अब फाइनल में जगह बनाने उतरेगी। घरेलू टीम की नजरें चौथी बार खिताब जीतकर इतिहास रचने पर भी होंगी। मुख्य कोच श्योर्ड मारिन के मार्गदर्शन में भारत ने टूर्नामेंट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों में 15 अंक के साथ अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। गत चैंपियन टीम ने इस दौरान 23 गोल किए और केवल चार गोल खाए। उसका गोल अंतर प्लस 19 रहा। भोपाल में भारतीय टीम के अभियान में उसकी आक्रमण की गहराई और रक्षात्मक मजबूती प्रमुख रूप से सामने आई है। इसी प्रदर्शन के दम पर भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में अपने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान पर पहुंचा।

दीपिका टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली आक्रमण खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। उन्होंने अब तक आठ गोल किए हैं और गोल करने वाली खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं। इसमें थाईलैंड और चीन के खिलाफ उनकी हैट्रिक भी शामिल है। हालांकि, भारतीय टीम का आक्रमण केवल दीपिका पर निर्भर नहीं रहा है। ललरेमसियामी, नवनीत कौर, मुमताज खान, नेहा, साक्षी राणा और सुनेलिता टोप्पो ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यपंक्ति में नवनीत ने मौके बनाने और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं, कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को सही खिलाड़ियों तक पहुंचाने, मैदान पर अपनी सक्रियता और नेतृत्व से टीम को मजबूती दी है। साक्षी, सुनेलिता और नेहा के योगदान ने भी दिखाया है कि भारतीय टीम मैदान के अलग-अलग हिस्सों से आक्रमण तैयार कर सकती है और गोल के मौके बना सकती है। इस विविधता ने कोच मारिन को तेज आक्रमण और रणनीतिक रूप से पेनल्टी कॉर्नर का इस्तेमाल करने के कई विकल्प दिए हैं। भारत के पेनल्टी कॉर्नर भी गोल हासिल करने का महत्वपूर्ण जरिया रहे हैं। इस मामले में दीपिका ने अहम भूमिका निभाई है। यदि मलेशिया रक्षात्मक रूप से पीछे रहकर भारतीय टीम को सर्कल में सीधे प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है, तो भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर की रणनीतियों में विविधता बनाए रखना जरूरी होगा। दूसरी ओर, भारतीय आक्रमण को रोकने के लिए मलेशिया को सर्कल में भारत की पहुंच सीमित करनी होगी और पेनल्टी कॉर्नर के मौके नहीं देने होंगे। मलेशिया की टीम पांच मैचों में सात अंक लेकर चौथे स्थान पर रही और नए आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगी। लीग चरण में उसने चीन के खिलाफ 2-2 से मुकाबला बराबर किया और दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया। इसके बाद अंतिम लीग मैच में थाईलैंड के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में मलेशिया ने खास जुझारूपन दिखाया।

बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स : सबिता टोप्पो ने बाधा दौड़ में जीता स्वर्ण, भारत के खाते में 30 पदक

भुवनेश्वर। ओडिशा की उभरती एथलीट और खेलो इंडिया की खिलाड़ी सबिता टोप्पो ने गुरुवार को यहां कलिंगा स्टेडियम में आयोजित बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिला 100 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक जीतकर घरेलू दर्शकों को झूमने का मौका दिया। सबिता ने 13.86 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारत की ही शाइनी ग्लैडसिया ने 14.03 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। श्रीलंका की पीजीएमएस गुनाथिलका 14.34 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही भारतीय दल के कुल पदकों की संख्या 30 हो गई, जिसमें 14 स्वर्ण, 12 रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। श्रीलंका चार स्वर्ण, पांच रजत और 12 कांस्य सहित 21 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश एक रजत और एक कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। नेपाल के खाते में एक रजत पदक है, जबकि भूटान और म्यांमार अभी तक पदक नहीं जीत सके हैं। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में शुरुआत में दो बार गलत स्टार्ट हुआ। दूसरी बार गलत शुरुआत के कारण ओडिशा की सुमाया जमान को प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। इसके बाद पांच खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सबिता ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और आसानी से स्वर्ण पदक जीत लिया। 21 वर्षीय सबिता ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण को दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं है, लेकिन स्वर्ण पदक उन्हें आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए बेहतर तैयारी की प्रेरणा देगा। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.75 सेकंड है, जो उन्होंने जून 2026 में कटक में सीनियर राज्य चैंपियनशिप के दौरान किया था। भारत के लिए दिन का पहला स्वर्ण पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में रोशन शेख ने जीता। उन्होंने 14.15 सेकंड का समय लिया। श्रीलंका के संदुन कोशल विजयरत्ने 14.37 सेकंड के साथ दूसरे और भारत के राहुल रितिक 14.48 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में भारत के वैभव ने 51.97 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया।

हॉकी इंडिया लीग का नया सत्र जनवरी के पहले सप्ताह से, खिलाड़ियों की नीलामी 7 दिसंबर को

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026-27 सत्र की प्रमुख तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा कर दी। प्रतियोगिता जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 7 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नए सत्र के लिए टीमों के गठन की दिशा में यह अगला बड़ा कदम होगा। आगामी सत्र में पुरुष वर्ग में छह और महिला वर्ग में चार फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। लीग के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतिभाओं को प्रमुख मंच उपलब्ध कराने की परंपरा जारी रहेगी। तैयारियां तेज होने के साथ ही फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के आपसी आदान-प्रदान और उन्हें टीम में बनाए रखने की प्रक्रिया पूरी करेंगी। इसके बाद उनका ध्यान नीलामी पर होगा। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, फ्रेंचाइजी को अपने प्रस्तावित खिलाड़ी आदान-प्रदान की जानकारी 29 नवंबर 2026 तक सीधे संबंधित फ्रेंचाइजी को देनी होगी। आधिकारिक ट्रेडिंग विंडो 29 नवंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे खुलेगी और 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे बंद होगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी को 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक खिलाड़ियों को स्थायी रूप से टीम से रिलीज करने की जानकारी हीरो हॉकी इंडिया लीग को देनी होगी और अपनी अंतिम टीम सूची जमा करनी होगी। उसी दिन शाम 5 बजे हीरो हॉकी इंडिया लीग सभी फ्रेंचाइजी को नीलामी के लिए तैयार संयुक्त खिलाड़ी सूची उपलब्ध कराएगी।

इसके बाद फ्रेंचाइजी के पास 3 दिसंबर को शाम 5 बजे तक उन खिलाड़ियों की सूची जमा करने का समय होगा, जिन्हें वे पिछले सत्र में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए पंजीकृत सूची से हटाना चाहती हैं। रांची रॉयल्स की पुरुष टीम और हीरो हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग काउंसिल की टीम के खिलाड़ी भी नीलामी की सूची में शामिल होंगे। भारतीय महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने लीग की वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि हीरो हॉकी इंडिया लीग एक और सत्र के लिए लौट रही है। यह लीग भारतीय खिलाड़ियों के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक महत्वपूर्ण मंच रही है।

क्राइस्टचर्च टेस्ट से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच ने गेंदबाजों को हड़बड़ी से बचने की दी सलाह

क्राइस्टचर्च। भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट से पहले अपनी टीम को गेंदबाजी में किसी तरह की 'बेचैनी' या हड़बड़ी से बचने की सलाह दी है। भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जीवित रखने के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी है। हालांकि, मोर्कल ने खिलाड़ियों से बाहरी दबाव को नजरअंदाज करने और सत्र दर सत्र अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है।

मोर्कल ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सबसे पहले, एक टीम के रूप में हमें 'बेचैनी' शब्द को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मुझे 'बेचैनी' शब्द पसंद नहीं है क्योंकि इससे खिलाड़ी मैदान पर जरूरत से ज्यादा कोशिश करने लगते हैं और अपनी गेंदबाजी की सही दिशा से भटक जाते हैं। इसलिए मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अगले सप्ताह हम बाहरी शोर और दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज करें। मैं आपको बताता हूं कि ये सभी खिलाड़ी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हम ईमानदारी से देखें तो यह चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसलिए हर खराब सत्र के बाद हमें इस बात में उलझना नहीं चाहिए कि अब हमें क्या-क्या करना है। उन्होंने आगे कहा, 'हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने, समस्याओं का समाधान निकालने और उसी दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। हम इस बारे में काफी बात करेंगे कि



मुकाबले को सत्र दर सत्र बांटकर कैसे खेलना है और किस तरह अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल सकते हैं। मोर्कल ने कहा कि दूसरे टेस्ट के लिए हेगले ओवल की पिच उन्हें काफी हरी नजर आ रही है लेकिन पिछले सप्ताह बेसिन रिजर्व की ऐसी ही दिखने वाली पिच से मिले अनुभव के बाद वह सतह को लेकर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते। उन्होंने कहा, 'मैंने जितना देखा है, उसके अनुसार पिच फिर काफी हरी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि वहां घास की परत थोड़ी लंबी है। हमें देखना होगा कि यह किस तरह खेलती है। जैसा मैंने कहा, पिछले मैच में सभी को उम्मीद थी कि पिच तेज और उछाल वाली होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमें बस कल पहले सत्र में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते समय सामने आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। वेलिंगटन की बेहद सपाट पिच पर भारत के चार तेज गेंदबाजों का आक्रमण प्रभाव नहीं छोड़ सका था। ऐसे में क्राइस्टचर्च में गुरनूर बरार को मौका मिल सकता है। वह अपनी गति और उछाल से गेंदबाजी आक्रमण को धार दे सकते हैं। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंद जल्दी नरम पड़ने की समस्या से निपटने में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है। मोर्कल ने गुरनूर को लेकर कहा, 'भारतीय टीम से जुड़ने के बाद से ही उसे लेकर काफी उत्साह है।

उसकी गति और उछाल इसकी वजह है। मुझे लगता है कि वह यहां की परिस्थितियों के लिए काफी उपयुक्त गेंदबाज होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने कहा, 'गुरनूर लगातार टीम में जगह बनाने के करीब पहुंच रहा है। वह सभी सही चीजें कर रहा है। लेकिन खिलाड़ी के तौर पर चयन ऐसी चीज है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे बस यह सुनिश्चित करना है कि मौका मिलने पर वह पूरी तरह तैयार रहे। कई बार जब आप मौके के करीब होते हैं तो गेंदबाज के तौर पर आपका ध्यान भटक सकता है। जब उसे मौका मिलेगा और यह भी तय नहीं है कि कब मिलेगा, तो मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि वह 100 प्रतिशत तैयार रहे। मोर्कल ने अंशुल कंबोज के प्रदर्शन को लेकर धैर्य रखने की भी अपील की। टेस्ट क्रिकेट में उनका शुरुआती सफर दो बेहद सपाट पिचों पर कठिन रहा है। पिछले साल इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल खिलाड़ियों की जगह टीम में शामिल किए गए कंबोज ने ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट पदार्पण किया था। उन्होंने 18 ओवर में 89 रन देकर एक विकेट लिया था।

आईएलटी20 : दुबई कैपिटल्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, डेजर्ट वाइपर्स को 45 रन से हराया

दुबई। दुबई कैपिटल्स ने डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 के पांचवें सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। बुधवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कैपिटल्स ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए डेजर्ट वाइपर्स को 45 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई कैपिटल्स ने सात विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स की टीम 17.5 ओवर में 119 रन पर सिमट गई।

दुबई कैपिटल्स की ओर से सैम बिलिंग्स ने 31 गेंदों पर 43 रन और रोवमैन पॉवेल ने 12 गेंदों पर तेजतर्रार 28 रन बनाए। गेंदबाजी में नूर अहमद ने चार विकेट लेकर सबसे अहम भूमिका निभाई। मुस्तफिजुर रहमान ने दो विकेट हासिल किए, जबकि दुश्मंथा चमीरा और हसन खान ने भी दो-दो विकेट लिए। डेजर्ट वाइपर्स की ओर से एंड्रिस गॉस ने सर्वाधिक 30 गेंदों पर 27 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दुबई कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मसूद गुरबाज दो गेंदों पर दो रन बनाकर फाफ डुप्लेसिस के साथ गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए। इस समय टीम का स्कोर आठ रन पर एक विकेट था। इसके बाद मैक्स होल्डन ने डुप्लेसिस के साथ मिलकर पावरप्ले तक पारी को संभाला। दोनों के बीच 34 गेंदों पर 37 रन की साझेदारी हुई। हालांकि, यह साझेदारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सातवें ओवर में वाइपर्स के कप्तान शादाब खान ने मैक्स होल्डन को कैच आउट करा दिया। इसके कुछ ही देर बाद डुप्लेसिस भी नांगेयालिया खान की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। वह अपनी पारी में पहला चौका लगाने की कोशिश कर रहे थे। 9.4 ओवर में 61 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद सैम बिलिंग्स और मार्कस स्टोइनिस ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 59 रन जोड़े। इस दौरान चौके लगाना आसान नहीं था, लेकिन बिलिंग्स ने 16वें ओवर में शादाब खान के खिलाफ एक छक्का और दो चौके लगाकर रन गति बढ़ाई। दुबई कैपिटल्स जब बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, तभी खुजैमा तनवीर ने 16.2 ओवर में स्टोइनिस को आउट कर दिया। इस समय टीम का स्कोर 120 रन था। तनवीर ने 19वें ओवर में बिलिंग्स और करीम जनत को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने तीन विकेट लेकर वाइपर्स की ओर से सबसे सफल गेंदबाज का प्रदर्शन किया। तीन पारियों में आठ विकेट के साथ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को दिए जाने वाला सफेद बेल्ट भी अपने नाम कर लिया। अंतिम ओवरों में रोवमैन पॉवेल ने तेजी से रन बनाते हुए दुबई कैपिटल्स को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 12 गेंदों पर 28 रन की पारी में दो चौके और दो छक्के लगाए। अंतिम ओवर में उन्होंने 16 रन बटोरे और टीम को 20 ओवर में सात विकेट पर 164 रन तक पहुंचा दिया। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेजर्ट वाइपर्स की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर में दुश्मंथा चमीरा ने बाबर आजम को दो गेंदों पर एक रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। टीम का स्कोर दो रन पर एक विकेट हो गया। इसके बाद फखर जमान और एंड्रिस गॉस ने 35 रन जोड़े।



सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : मुंबई की लगातार छठी जीत, पुडुचेरी और हरियाणा ने आखिरी ओवर में दर्ज की जीत

नई दिल्ली। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए उत्तराखंड को 86 रन से हरा दिया। मुशीर खान के 40 गेंदों पर 65 रन की पारी ने मुंबई को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक तामोरे ने 14 गेंदों पर 39 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को शुरुआती गति दी, जबकि अंगकृष रघुवंशी ने 51 रन बनाए। मुंबई की टीम अंतिम ओवर में 209 रन बनाकर ऑलआउट हुई। उत्तराखंड की ओर से रविंदर नेगी और जगदीशा सुचित ने तीन-तीन विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 58 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गई। इसके बाद शाश्वत डांगवाल ने 20 गेंदों पर 37 रन और जगदीशा सुचित ने 19 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया। हालांकि, अथर्व अंकोलेकर ने निचले क्रम को समेटते हुए 17 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। उत्तराखंड की टीम 16.5 ओवर में 123 रन पर सिमट गई। यह सात मैचों में मुंबई की छठी जीत है। उसका एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस प्रदर्शन के साथ मुंबई ग्रुप डी में शीर्ष स्थान पर मजबूती से कायम है। कर्नाटक ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर बड़ौदा को आठ विकेट से हराया। बड़ौदा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रीशा आचार और विद्वत कावेरप्पा ने चार-चार विकेट हासिल किए। शाश्वत रावत ने 31 रन बनाए, जबकि ध्रुव पटेल ने 33 रन का योगदान दिया। हालांकि, 31 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद बड़ौदा की टीम दबाव से उबर नहीं सकी। जवाब में कर्नाटक ने रोहन पाटिल के 48 और कृष्णन श्रीजित के 33 रन की मदद से पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। इसके बाद करुण नायर ने 20 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाकर टीम को 16.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य तक पहुंचा दिया। कर्नाटक ने 23 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। पुडुचेरी ने मध्य प्रदेश को दो विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। उसने 158 रन का लक्ष्य दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश की टीम 25 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, लेकिन हर्ष गवाली ने 48 गेंदों पर नाबाद 72 रन की पारी खेलकर टीम को सात विकेट पर 157 रन तक पहुंचाया। प्रणय सिंह ने 29 रन देकर चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पुडुचेरी के परमेश्वरन शिवरामन ने 30 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वेदांत भारद्वाज ने 26 और गौतम दिलीप शास्त्री ने 35 रन का योगदान दिया। शिवांग कुमार ने तीन विकेट लिए, लेकिन वह मध्य प्रदेश को हार से नहीं बचा सके। इस हार के साथ मध्य प्रदेश ने लगातार दो पराजयों के साथ ग्रुप चरण का समापन किया। हरियाणा ने जम्मू-कश्मीर को दो विकेट से हराकर उसकी लगातार तीन जीत का सिलसिला रोक दिया। जम्मू-कश्मीर ने अब्दुल समद के 45 गेंदों पर नाबाद 77 रन की बदौलत नौ विकेट पर 167 रन बनाए।

एक नजर

पुतिन से ट्रंप की अपील, यूरोप में सैन्य आक्रामकता रोकें और यूक्रेन से करें समझौता



वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूरे यूरोप में सैन्य आक्रामक गतिविधियां रोकने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द समझौता हो सकता है और इससे युद्ध में हो रही जनहानि पर विराम लगेगा। ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने बताया कि चीन में पुतिन के साथ हुई चर्चा के दौरान उन्होंने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में रूस की सैन्य गतिविधियों को रोकने का मुद्दा उठाया था। ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने पुतिन से कहा कि वह यूरोप के विभिन्न हिस्सों में जारी सैन्य आक्रामकता को समाप्त करें। ट्रंप ने कहा कि उनकी अपील का उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच जल्द समझौते की राह तैयार करना है। उन्होंने इसे एक मजबूत संभावना बताते हुए कहा कि हर महीने हजारों लोगों की जान जा रही है और युद्ध में भारी तबाही हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द समझौता होने से इस रक्तपात को रोका जा सकेगा। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब नाटो के पूर्वी हिस्से में स्थित एस्टोनिया, डेनमार्क और पोलैंड समेत कई देशों से जुड़े सुरक्षा घटनाक्रमों को लेकर रूस की गतिविधियों पर चिंता जताई जा रही है।

यूक्रेन पर रूसी हमले का नया खतरा, जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से मांगी पैट्रियट मिसाइलें



कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि रूस उनके देश पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस बार भी ऊर्जा प्रतिष्ठानों, परिवहन एवं रसद ढांचे और आवश्यक सेवाओं को निशाना बनाया जा सकता है। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से यूक्रेन को अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियां और इंटरसेप्टर मिसाइलें जल्द उपलब्ध कराने की अपील की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि दुर्भाग्य से रूस एक नए बड़े हमले की तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार देश का ऊर्जा ढांचा एक बार फिर रूसी हमले का प्रमुख निशाना बन सकता है। उन्होंने बताया कि रूसी हमलों में बिजली सबस्टेशनों, ओवरहेड बिजली लाइनों और पूरे पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद मरम्मत दल बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ऊर्जा ढांचे पर हमलों से आम लोगों की जिंदगी और आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अतिरिक्त वायु रक्षा सहायता को लेकर अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ हुई बातचीत पर विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका निर्मित पैट्रियट और नासाम्स वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति को प्राथमिकता बताया। इस बीच, यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता जारी रखने के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के नेता ब्रसेल्स में बैठक कर रहे हैं। बैठक में संघ के अगले दीर्घकालिक बजट पर भी चर्चा हो रही है। यूरोपीय आयोग ने वर्ष 2027 में यूक्रेन को 45 अरब यूरो का अतिरिक्त ऋण देने का प्रस्ताव रखा है।

नेपाल मंत्रिमंडल के प्रोटोकॉल में बड़ा फेरबदल, सोबिता गौतम सातवें से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंचीं



काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के वरीयता क्रम में संशोधन किया है। नए फैसले के तहत कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री सोबिता गौतम को मंत्रिमंडल में सातवें स्थान से ऊपर उठाकर तीसरे स्थान पर रखा गया है। इससे पहले मंत्रिमंडल की वरीयता सूची में विदेश मंत्री शिशिर खनाल तीसरे स्थान पर थे। अब सोबिता गौतम ने उनकी जगह ले ली है। गौतम की पदोन्नति के बाद ऊर्जा मंत्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, गृह मंत्री सुदन गुरुङ और भौतिक पूर्वाधार एवं परिवहन मंत्री सुनील लम्साल की वरीयता में एक-एक स्थान की गिरावट आई है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के महाधिवेशन में सोबिता गौतम पार्टी की उपसभापति निर्वाचित हुई थीं। पार्टी के संगठनात्मक वरीयता क्रम में वह तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, मंत्रिमंडल गठन के समय उन्हें सातवें स्थान पर रखा गया था।

यरुशलम की कोर्ट के रुख से नेतान्याहू के बेदाग होने की उम्मीद बढ़ी

यरुशलम,एजेंसी। इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यरुशलम जिला अदालत का रुख राहत देने वाला है। अदालत ने बुधवार को रिश्वत लेने और अन्य आरोपों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अभियोजन को सलाह है कि वह नेतन्याहू से समझौता कर ले। अदालत की इस टिप्पणी के तत्काल बाद नेतन्याहू ने मुकदमे को खत्म करने की मांग की। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने गुस्से भरे भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार के मुकदमे ने उनके परिवार और स्टाफ की जिंदगी 'बर्बाद' कर दी है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें काम करने से रोकना चाहते हैं। उनसे अपील की कि विपक्ष उनके साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ले।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार तीन जजों की टिप्पणी आने के फौरन बाद नेतन्याहू ने शाम को यरुशलम में नेसेट (इजराइली संसद) से टीवी पर बयान दिया। इससे पहले उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई कर रहे जजों ने उन पर लगे सबसे गंभीर आरोपों पर संदेह जताया और अभियोजकों को समझौता करने की सलाह दी। जिला अदालत की सलाह के बाद नेतन्याहू ने बयान में दावा किया कि सत्ता से हटाने की इस अलोकतांत्रिक कोशिश ने उनके परिवार और देश के 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'आज यह मुकदमा बिखर गया है। दस साल पहले मैंने कहा था



कि कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इस सच्चाई को सबके सामने आने में 10 साल लग गए।' उन्होंने कहा कि यह मुकदमा तुरंत खत्म होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जजों ने यह भी संकेत दिया कि एक अन्य मामले में शायद कोई अपराध हुआ ही नहीं है। मुकदमा शुरू होने के छह साल से भी अधिक समय बाद आया यह बयान अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। जजों की टिप्पणी को नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने अपनी बेगुनाही साबित होने के रूप में देखा है। नेतन्याहू पर तीन मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत का आरोप है। उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अदालत से बिना कोई अपराध स्वीकार किए औपचारिक रूप से माफी की मांग की थी। अपने संबोधन में इजराइल की अगली सरकार के गठन को लेकर चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने विरोधियों से अपील की कि वे उनके साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे आएं।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भाषण के अंत में कहा, 'बहिष्कार को इसी वक्त खत्म होना चाहिए। मुझे पता है कि इजराइल के सामने कितने बड़े और तात्कालिक खतरे हैं। इनसे निपटने का केवल एक ही तरीका है— एकजुट होना। इजराइल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें एक क्षण भी गंवाए एकजुट होना होगा।' नेतन्याहू पर आरोप तय होने की प्रक्रिया एक दशक से भी पहले शुरू हुई थी। नेतन्याहू का मानना है कि उसके बाद के साल उनके परिवार और करीबी सहयोगियों के लिए बेहद कठिन और उत्पीड़न भरे रहे। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे यरुशलम में शांति से सार्वजनिक जीवन नहीं जी सके। उन्होंने कहा, 'मेरे, मेरी पत्नी और मेरे बेटों के लिए ये 10 साल भयानक पीड़ा के रहे हैं। बेतुकी पूछताछ, चरित्र हनन और आत्मा को गहरी चोट पहुंचाने वाले उकसावे के वर्ष। हमारे वे 10 साल हमें कौन वापस देगा? न्होंने कहा कि उनके राजनीतिक सहयोगियों को जबरन पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां उन्हें ब्लैकमेल करके आपराधिक काम करने के लिए मजबूर किया गया और अपमानित किया गया। कई लोगों की जिंदगी बरबाद हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि वे मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे सकें। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि दशकों तक सार्वजनिक पदों पर रहने के बावजूद उन्हें 'इजराइल का प्रधानमंत्री' नहीं कहा गया। इसके बजाय, उन्होंने कहा, 'मैं प्रतिवादी नंबर 1' बना रहा। नेतन्याहू ने विरोधियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे 'ईरान और उत्तर कोरिया' जैसी सरकारों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुलासा किया कि विरोधियों की मिलीभगत से संसद ने एक विधेयक को आगे बढ़ाया, जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों को सरकार बनाने से रोकेगा। उन्होंने कहा कि विरोधियों को उम्मीद थी कि अदालत का फैसला मेरे खिलाफ आएगा।

बांग्लादेश में दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, एक पर गोपालगंज हिंसा में शामिल होने का आरोप

ढाका। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा ने दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 25वें बैच के अधिकारी मो. अबुल कलाम आजाद और दूसरे 33वें के मो. रकीबुल हसन हैं। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त (खुफिया) शफीकुल इस्लाम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) ने अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा था।

प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम ने रकीबुल हसन को गिरफ्तार करने के कारणों कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि अबुल हसन पर गोपालगंज में हाल ही में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। अबुल हसन 'स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन-14' की भैरब कंपनी में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। उनका घर गोपालगंज के मुक्सुदपुर उपजिला के गोविंदपुर में है। रकीबुल हसन भी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। उधर, भारत में रह रहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश लौटने के इरादे की घोषणा और अवामी लीग के बंद के दौरान हिंसा की आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि आंतरिक जानकारी लीक करने और हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में मिलीभगत के आरोपों के संबंध में कुछ और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने बुधवार को सात जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए। इनमें से पांच जिले अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं।

इससे पहले, गोपालगंज सहित ढाका रेंज के 13 जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक रैंक के 12 अधिकारियों को दो महीने के लिए तैनात किया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विभिन्न इकाइयों में नया नेतृत्व लाकर फील्ड स्तर पर पुलिस बल का पुनर्गठन किया जा रहा है। बताया गया है कि गिरफ्तार दोनों पुलिस अधिकारी जुलाई, 2024 के जन-विद्रोह से पहले ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस में तैनात थे। गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बल के भीतर निगरानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कुछ अधिकारी 'फासीवादी ताकतों' से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कड़ी निगरानी रख रही है।

बांग्लादेश में अवामी लीग की मदद के आरोप में पुलिस अफसर गिरफ्तार, 101 बैंक खाते फ्रीज

ढाका,एजेंसी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 27 और 28 नवंबर के देशव्यापी बंद के आह्वान से तारिक रहमान सरकार की नींद उड़ी हुई। हसीना के गृह जनपद गोपालगंज की हालिया हिंसा की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अवामी लीग को पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों ने उकसाया। इस समय लीग नेताओं को पैसा भी दिया जा रहा है। इस आरोप में पुलिस की विशेष इकाई 'स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन' (एसआरबी) के एक कंपनी कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एनबीआर) ने हिंसा को आर्थिक मदद देने और समर्थन करने के आरोपों के चलते 97 व्यक्तियों और चार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनमें एक पूर्व सचिव, प्रतिबंधित अवामी लीग के नेता और जन प्रतिनिधियों के खाते शामिल हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजस्व खुफिया विभाग की कार्रवाई से इस हिंसा के पीछे की साजिश का एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है।

जांचकर्ता दो सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों की आड़ में की गई तोड़फोड़ के पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था और क्या प्रशासन के भीतर ऐसे लोग थे जिनके राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण से यह सब हुआ? खुफिया सूत्रों का कहना है कि केवल उन लोगों को गिरफ्तार करने से तोड़फोड़ की घटनाओं को दोबारा होने से नहीं रोका जा सकता, जिन्होंने सीधे तौर पर हमलों को अंजाम दिया।



इसलिए, हिंसा के पीछे के संभावित आयोजकों, आर्थिक मदद देने वालों और सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक खातों को फ्रीज करना और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी करना इसी जांच का हिस्सा है। गोपालगंज में प्रतिबंधित अवामी लीग के हालिया कार्यक्रमों के दौरान हुई व्यापक तोड़फोड़ और हिंसा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या मुकसूदपुर पुलिस स्टेशन में आगजनी के बाद, तोड़फोड़ में शामिल लोगों का पुलिस या प्रशासन के भीतर किसी व्यक्ति से संपर्क था या उन्हें वहां से कोई मदद मिली। फरीदपुर क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तोड़फोड़ के मामले में खुफिया निगरानी में रखा गया है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने तोड़फोड़ में मदद करने के लिए अपने पद, ओहदे और प्रभाव का इस्तेमाल किया, या जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन करने में निष्क्रिय रहे, जिससे हिंसा का मौका बन गया। हालांकि अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (अपराध और संचालन) अहसान हबीब पलाश ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितने लोग निगरानी में हैं। इस बीच मुक्सूदपुर पुलिस स्टेशन में आगजनी की घटना के बाद चर्चा में आए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. अबुल हसन को 23 नवंबर की रात ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने मैमनसिंह स्थित एसआरबी-14 कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना गुरुवार सुबह एक सूत्र ने दी।

नेपाल में 13 साल के बच्चों को भी काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विवाद

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में 13 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को कुछ निर्धारित हल्के काम करने की अनुमति देने के सरकारी प्रस्ताव पर संसद की समिति में विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) विधेयक-2026 में माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से 13 साल के बच्चों को सीमित काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, विपक्षी सांसदों ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का श्रम या रोजगार कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसदों के बीच इस बात को लेकर मतभेद सामने आए कि नेपाल में रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र 13 साल होनी चाहिए या 15 साल। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने सरकारी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि नेपाल में अभी भी लगभग 11 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। सरकार का उद्देश्य इस संख्या को कम करना है। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाकर बच्चों के काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं है। गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियों और अभिभावकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं के कारण कई बच्चे काम करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में जब तक राज्य उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होता, तब तक केवल पूर्ण प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक तैयार करते समय बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास, गरीबी, पारिवारिक स्थिति तथा कानून लागू करने की सरकारी क्षमता को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा, 'हमने वैज्ञानिक आधार पर 13 साल की उम्र निर्धारित की है। केवल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रावधानों का अनुसरण करने के बजाय नेपाल की परिस्थितियों के अनुसार यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल विकास से संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि इसमें 13 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बच्चे और उनके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से उन्हें अनुसूची-1 में निर्धारित हल्के काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। यह काम स्कूल के समय से पहले या बाद में अथवा छुट्टियों के दौरान ही किया जा सकेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित अनुसूची में पांच श्रेणियों के तहत कई तरह के काम शामिल किए गए हैं। समिति के सभापति रहबर अंसारी ने कहा कि विधेयक को अधिक प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए और बच्चों से काम कराने वाले नियोक्ताओं के लिए इसे आर्थिक रूप से महंगा बनाया जाना चाहिए। बाल श्रम सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का माध्यम है, इसलिए जुर्माना, कानूनी जवाबदेही और पुनर्वास के प्रावधान मजबूत होने चाहिए। उन्होंने बताया कि समिति अब सांसदों की ओर से दर्ज संशोधन प्रस्तावों पर धारा-दर-धारा चर्चा करेगी और विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों तथा संबंधित मंत्रालय के साथ भी विचार-विमर्श करेगी। हालांकि प्रस्तावित विधेयक का सत्तारूढ़ दल के कुछ सांसदों ने भी विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसदों ने विधेयक में बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने की मांग की। सांसद सोम शर्मा ने कहा कि बाल श्रम का सीधा संबंध गरीबी, अभिभावकों की सुरक्षा की कमी और परिवार की आर्थिक स्थिति से है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम आय वाले परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर न हों। आरएसपी सांसद प्रभा कार्की ने कहा कि बाल श्रम से बचाए गए बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य को तत्काल लेनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षित आवास, स्कूलों में पुन: दाखिला और घरेलू बाल श्रम पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की। बाल श्रम कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सांसद प्रकाश पाठक ने शरणार्थी बच्चों और नेपाल की खुली सीमा के रास्ते आने वाले बच्चों को भी बाल श्रम से बचाने के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता बताई। उधर, विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठ ने कहा कि पहले सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक दिखाई देने वाला बाल श्रम अब धीरे-धीरे छिपे हुए स्थानों पर होने लगा है। उन्होंने इसके पीछे के कारणों की जांच करने की जरूरत बताई। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं, माता-पिता के विदेश पलायन, अभिभावकों की मृत्यु, आवासीय संस्थानों से बच्चों के बाहर आने और शिक्षा में असमान पहुंच को बाल श्रम बढ़ने के प्रमुख कारणों में शामिल किया।

इन कार्यों की अनुमति-

बीज बोना, पौधे लगाना, किचन गार्डन में पानी देना, निराई-गुड़ाई करना, फूल एवं फल तोड़ना, पशुओं को चारा देना तथा दूध निकालने में सहायता करना।

घर की सफाई, हल्के बर्तन धोना, खाना बनाने में सहायता, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल और हल्का सामान लाना।

ऊन कातना, बुनाई करना, टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाना, सामान्य सिलाई, कपड़ों में बटन लगाना और फूलों की माला बनाना।

दुकानों में सामान व्यवस्थित करना, सामान्य सफाई, दस्तावेजों की फाइलिंग, सामान वितरित करना, बिल बनाना, हिसाब-किताब में सहायता, पुस्तकालय और कार्यालय में सहयोग तथा टेलीफोन रिसीव करना।

सार्वजनिक उद्यानों और स्कूल परिसरों की सफाई, पुस्तकालय में किताबें व्यवस्थित करना, छोटे बच्चों को पढ़ाना, साक्षरता अभियान में सहयोग तथा धार्मिक, सांस्कृतिक और स्कूल के सुरक्षित नाट्य कार्यक्रमों में भाग लेना।

काम के घंटे भी होंगे निर्धारित-

विधेयक में अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए काम करने की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

- 13 से 15 साल के बच्चे प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे और सप्ताह में 12 घंटे काम कर सकेंगे।

- 15 से 18 साल के किशोर प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे और सप्ताह में 36 घंटे काम कर सकेंगे।

इसके अलावा बच्चों से शाम 6 से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कराया जा सकेगा। लगातार तीन घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सप्ताह एक दिन का सवैतनिक अवकाश भी देना होगा। नियोक्ताओं को बच्चों को काम पर रखने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से काम के लिए अनुपयुक्त पाए जाने वाले बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा सकेगा।

क्या है विपक्ष की मांग-

नेपाली कांग्रेस के सांसदों रेखा कुमारी यादव, कालीबहादुर सहकारी, हरिनादेवी कामी और निनु कुमारी कर्ण ने विधेयक में संशोधन प्रस्ताव दर्ज कराते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के श्रम और रोजगार से पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की है। वहीं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रमेश कुमार मल्ल ने न्यूनतम कामकाजी उम्र 13 से बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव दिया है। सीपीएन (यूएमएल) के सांसद कृपाराम राणा ने संविधान के अनुच्छेद 39(4) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के कन्वेंशन नंबर 138 का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि क्या प्रस्तावित विधेयक बच्चों के संवैधानिक अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप है।

एक नजर

एनएलएमसी ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की 1300 करोड़ की संपत्ति को भुनाने का बनाया नया प्लान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों की अतिरिक्त संपत्तियों को भुनाकर राजस्व जुटाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसी के तहत राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ने अपनी 22वीं बोर्ड की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) से जुड़े लगभग 1,300 करोड़ रुपये के नए परिसंपत्ति मुद्रीकरण और मूल्यांकन प्रस्तावों पर विचार किया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार एक बयान में कहा कि एनएलएमसी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के तहत बुधवार को नई दिल्ली में निदेशक मंडल की 22वीं बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों, स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों, सरकार-से-सरकार (जी2जी) लेन-देन, एनएलएमसी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के मुद्रीकरण, हाल ही में आयोजित ई-नीलामी के परिणामों तथा निगम को संस्थागत रूप से और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित लगभग 1,300 करोड़ रुपये के संयुक्त आकलित मूल्य वाले नए परिसंपत्ति मुद्रीकरण और मूल्यांकन प्रस्तावों पर विचार किया। इन प्रस्तावों को निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए विचारार्थ लिया गया। ये प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएलएमसी द्वारा 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों के सफल मुद्रीकरण के अतिरिक्त हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ, एनएलएमसी अपनी स्वयं की परिसंपत्तियों को भी बाजार में उतार रही है। बोर्ड ने नई दिल्ली और मुंबई स्थित एनएलएमसी के स्वामित्व वाली 17 आवासीय संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया।

एन चंद्रशेखरन की तीसरी बार नियुक्ति के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा टाटा ट्रस्ट

नई दिल्ली। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और आरडी टाटा ट्रस्ट (आरडीटीटी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में टाटा संस और उसके 6 निदेशकों के खिलाफ गुरुवार को मुकदमे दायर किए हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ शुक्रवार को इन मुकदमों पर सुनवाई कर सकती है। कोर्ट में टाटा ट्रस्ट की ओर से दायर मुकदमों के अनुसार एन. चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त करने के लिए टाटा संस के निदेशक मंडल की 17 सितंबर का पारित प्रस्ताव अमान्य था। ट्रस्ट ने कहा कि इसे कंपनी के अंतर्नियमों (एओए) के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी समर्थन में मत नहीं मिला था। दोनों ट्रस्ट ने एन. चंद्रशेखरन को कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी है। एसडीटीटी ने 50 करोड़ रुपये और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। दोनों ट्रस्ट ने इस राशि पर सालाना 18 फीसदी ब्याज भी मांगा है। ट्रस्ट ने तत्काल राहत के तौर पर यह मांग की है कि 30 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में नामित निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में टाटा संस के चेयरमैन अपने निर्णायक मताधिकार का इस्तेमाल न कर सकें। यह विवाद 17 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में चंद्रशेखरन को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन अगले पांच साल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने के बाद शुरू हुआ। इससे पहले दोनों ट्रस्ट ने बुधवार रात हाई कोर्ट जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उनका कहना है कि 17 सितंबर के बाद से इस मामले में भेजे गए पत्रों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ट्रस्ट ने 17 सितंबर को पारित निदेशक मंडल के प्रस्ताव को चुनौती दी है। ट्रस्ट ने 20 सितंबर को जारी एक बयान में कहा था कि यह प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं हुआ और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।



भारत की संप्रभुता किसी व्यक्ति, परिवार या जाति विशेष में नहीं, आम नागरिक में निहित: मुख्यमंत्री



लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की संप्रभुता किसी व्यक्ति, परिवार या जाति विशेष में नहीं, बल्कि देश के आम नागरिक में निहित है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार और दायित्व दिया है कि वह देश का वास्तविक संरक्षक है। कोई व्यक्ति या परिवार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके कारण भारत अस्तित्व में है या वही भारत का संरक्षक है। भारत का हर नागरिक संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की रक्षा का उत्तरदायी है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित संविधान गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान हम सबका गौरव और 145 करोड़ भारतवासियों का मार्गदर्शक है। यह हमें अधिकारों का स्मरण कराने के साथ कर्तव्यों का बोध भी कराता है और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का अहसास कराता है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस विचार को ध्यान में रखा था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतवासी स्वयं तय करेंगे। इसी भावना से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया के उन विशिष्ट संविधानों में है, जिसने पहले दिन से ही बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा और लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार प्रदान किया। दुनिया के कई ऐसे देश, जो स्वयं को लोकतंत्र का बड़ा समर्थक बताते हैं, वहां लंबे समय तक रंगभेद और लिंगभेद के आधार पर नागरिकों को समान अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन भारत ने संविधान लागू होने के पहले दिन से ही प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करके लाल पुस्तिका लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उन्होंने संविधान की प्रति पढ़ी होती तो शायद भारत की संप्रभुता के संरक्षक होने का दावा करने का दुस्साहस नहीं करते।

जब उन्हें अवसर मिला था, तब उन्होंने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया। आजादी के तत्काल बाद पहला संविधान संशोधन प्रेस की आजादी को बंधक बनाने के लिए किया गया। समय-समय पर अपने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए गए। इन लोगों ने केवल संविधान ही नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को भी कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। भारत पर लगातार आक्षेप लगाए और लोकतंत्र को कमजोर करने के षड्यंत्र किए। ऐसे लोगों के प्रयासों से सावधान रहना होगा। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशों से देश को बचाना हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को कभी भारत रत्न नहीं लेने दिया। उन्हें संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए भी प्रयास किए गए और उन्हें चुनाव हराने के लिए तमाम षड्यंत्र किए गए।

जनसत्ता दल ने 2027 की चुनावी जंग के लिए खोले पत्ते, प्रतापगढ़ की तीन सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने प्रतापगढ़ में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरुवार को जिले की तीन विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुंडा से वह स्वयं चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि बाबागंज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मौजूदा विधायक विनोद सरोज और विश्वनाथगंज से कुलदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है।

राजा भैया ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी नेतृत्व ने आपसी विचार-विमर्श के बाद तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इसके तहत कुंडा विधानसभा क्षेत्र से वह स्वयं चुनाव लड़ेंगे। बाबागंज से मौजूदा विधायक विनोद सरोज को दोबारा मौका दिया गया है। वहीं, विश्वनाथगंज से पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी कुलदीप पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कुलदीप पटेल की पत्नी माधुरी पटेल वर्तमान में प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कुलदीप पटेल परमेश्वर प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज, मालाधर छत्ता के प्रधानाचार्य भी हैं। वह वर्ष 2010 में क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2015 में ग्राम प्रधान निर्वाचित हो चुके हैं।

राजा भैया ने कहा कि पार्टी ने संगठन और जनाधार को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता अभी से तैयारियों में जुटेंगे और जनता के बीच जाकर संगठन की नीतियों एवं उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। उल्लेखनीय है कि कुंडा विधानसभा सीट रघुराज प्रताप सिंह का परंपरागत राजनीतिक गढ़ रही है। वह वर्ष 1993 से लगातार इस सीट से विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं और अब तक सात बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं, बाबागंज से विनोद सरोज मौजूदा विधायक हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने कुंडा और बाबागंज दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। तीन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ में अपनी शुरुआती रणनीति स्पष्ट कर दी है। अब जिले की शेष विधानसभा सीटों पर पार्टी के रुख को लेकर राजनीतिक हलकों में नजरें टिकी हैं।

जे.पी. नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- अबोध को इतिहास की खबर नहीं



अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने गुरुवार को संविधान गौरव दिवस पर अहमदाबाद के टैगोर हॉल में भाजपा की ओर से आयोजित 'प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन' में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि 'अबोध को इतिहास की खबर नहीं' और वह दिनभर 'वोट चोर... वोट चोर' करता रहता है। नड्डा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1949-50 में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी और भाजपा ने केवल उनकी सोच को अमल में लाने का काम किया है। प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 370 लागू करने का विरोध किया था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद इसे लागू कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस डॉ. आंबेडकर की विरोधी रही है। कांग्रेस ने ही उन्हें संविधान सभा में चुने जाने से रोकने का प्रयास किया था। नड्डा ने कहा कि डॉ. आंबेडकर को भारत रत्न भी भाजपा समर्थित वी.पी. सिंह सरकार के कार्यकाल में दिया गया था। नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक 'अबोध बालक' दिनभर 'वोट चोर... वोट चोर' करता रहता है और लाल पुस्तक लेकर घूमता है, लेकिन उसे संविधान के एक अक्षर की भी जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने से रोकने का प्रयास किया था। नड्डा ने दावा किया कि वोट चोरी कांग्रेस ने की थी और डॉ. आंबेडकर के बैलेट पेपर की चोरी कर उन्हें हराया गया

एमएमडीआर संशोधन बिल लागू होने से झारखंड को हर साल 13 हजार करोड़ राजस्व का होगा नुकसान : हेमंत सोरेन

रांची,एजेंसी। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की ओर से संकल्प पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सदन को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के खिलाफ संकल्प पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक के लागू होने झारखंड को प्रतिवर्ष 13 हजार करोड रुपए के राजस्व होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम से राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर कर, उपकर एवं सेस लगाने की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, पूर्व में लगाए गए ऐसे करों के बकाये और वसूली नहीं की गई राशि के दावों को भी अमान्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 हजार करोड़ रूपये के राजस्व नुकसान से राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाई होगी। इसका सीधा असर राज्य के विकास और आम जनता के हित में संचालित योजनाओं पर पड़ेगा। खनन का नुकसान झेलने वाले समुदायों के विकास में खर्च होना चाहिए। खनिज से प्राप्त राजस्व मुख्यमंत्री ने संकल्प में झारखंड की खनिज संपदा और यहां की सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड देश के सबसे खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। साथ ही यह आदिवासी बहुल राज्य भी



है। राज्य के अधिकांश खनन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं। खनन गतिविधियों से होने वाले नुकसान का सबसे अधिक दंश भी इन्हीं समुदायों को झेलना पड़ता है।उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विस्थापन, जमीन से बेदखली, पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च किया जाना न्यायसंगत है। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प में सर्वोच्च न्यायलय के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खनिजयुक्त भूमि भी भूमि है और संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-49 के तहत राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। कर की गणना के लिए खनिज के मूल्य या उत्पादन को आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप है। खनन से प्रभावित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए खनिज राजस्व का एक हिस्सा खर्च करना कल्याणकारी राज्य का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी संवैधानिक और न्यायिक पृष्ठभूमि में झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक-2024 पारित किया था, जिसे राज्य सरकार ने अधिनियमित किया। इससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है।

दुनिया की नंबर 1 लुब्रिकेंट्स सप्लायर शेल ने भारत में नई सिंथेटिक रेंज किया लॉन्च, बेहतर परफॉर्मेंस और इंजन सुरक्षा पर जोर



नई दिल्ली,एजेंसी। लगातार 20 साल से दुनिया की नंबर वन लुब्रिकेंट्स सप्लायर (क्लाइन) शेल लुब्रिकेंट्स ने गुरुवार को भारत में अपनी नई सिंथेटिक लुब्रिकेंट रेंज लॉन्च की है। इसमें शेल हेलिक्स, शेल एडवांस और शेल रिमुला ब्रांड शामिल हैं। शेल लुब्रिकेंट्स के इस नई रेंज को पेश करते हुए शेल लुब्रिकेंट्स एंड राज पेट्रो स्पेशियलिटीज की दक्षिण एशिया प्रमुख देबांजलि सेनगुप्ता ने कहा कि यह प्रोडक्ट भारत के ऑटोमोटिव सेगमेंट में बेहतर वैल्यू, शानदार परफॉरमेंस और बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती है। यह वाहनों में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और भारत की परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस पोर्टफोलियो में शेल की सिंथेटिक लुब्रिकेंट टेक्नोलॉजी को भारतीय परिस्थितियों के लिए परखी गई एडवांस्ड ग्लोबल स्पेशिफिकेशंस के साथ मिलाया गया है, जिससे इंजन की ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित हो, परफॉर्मेंस बढ़े और ज्यादा वैल्यू मिले। इस रेंज का लक्ष्य ग्राहकों को ईंधन दक्षता, बेहतर परिचालन, मेंटेनेंस की कम जरूरत और इंजन की लंबी उम्र के जरिये अपने हर सफर का ज्यादा आनंद लेने में सक्षम बनाना है।

सेनगुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, 'भारत वैश्विक स्तर पर शेल लुब्रिकेंट्स के प्रमुख बाजारों में शामिल है और हमें भारतीय आफ्टरमार्केट के लिए अपनी नई सिंथेटिक पोर्टफोलियो रेंज को लॉन्च करते हुए गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ये नई रेंज व्यापक परीक्षण, गहन तकनीकी विशेषज्ञता और लुब्रिकेंट टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी सतत प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस नए पोर्टफोलियो के जरिए हम भारत में अधिक से अधिक ग्राहकों तक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी की पहुंच आसान बना रहे हैं। उपभोक्ताओं की गहरी समझ पर आधारित हमारा यह बेहतर वैल्यू वाला पोर्टफोलियो ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों और उनके अलग-अलग सफर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है।

नेक्स्ट जनरेशन सिंथेटिक पोर्टफोलियो में चार उत्पाद हैं, जिन्हें पैसेंजर कार, मोटरसाइकिल और कॉमर्शियल व्हीकल्स की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है-

शेल हेलिक्स एक्स्ट्रा एचएक्स8 0डब्ल्यू-16 : कंपनी के चीफा मार्केटिंग ऑफिसर अंकिता मेहरा ने बताया कि यह पूरी तरह से सिंथेटिक, बीएस-6 मानकों के अनुरूप पैसेंजर कार इंजन ऑयल है। इसे आधुनिक एवं हाइब्रिड पावरट्रेन को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शेल की एंटी-फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी से लैस यह इंजन ऑयल नवीनतम एपीआई एसक्यू और आईएलएसएसी जीएफ-7बी मानकों के अनुरूप है। यह ईंधन दक्षता बढ़ाने और इंजन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, जिससे वाहन सालाना 440 किलोमीटरख तक अतिरिक्त दूरी तय कर सकता है। मेहरा ने कहा कि ग्राहकों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें ईंधन पर होने वाले खर्च में बचत और इंजन की बेहतर प्रतिक्रिया का लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्हें यह भरोसा भी मिलेगा कि आधुनिक एवं हाइब्रिड पावरट्रेन वाले उनके इंजन लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। यह इंजन ऑयल 894 रुपये प्रति लीटर की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर 1 लीटर और 3.5 लीटर के पैक में उपलब्ध है।

शेल एडवांस एक्स्ट्रा एएक्स7: शेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अमित घुमरे ने बताया कि यह एक प्रीमियम, पूरी तरह से सिंथेटिक मोटरसाइकिल इंजन ऑयल है, जिसे मिड-वेट रिक्रिएशनल और क्रूजर मोटरसाइकिलों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी से लैस इस इंजन ऑयल को रोजाना के सफर और लंबी राइड के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया एवं लगातार अच्छा प्रदर्शन देने के लिए विकसित किया गया है। अमित घुमरे ने कहा कि इसे 15,000 किलोमीटर तक इंजन की पावर में कोई कमी नहीं आने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये इंजन ऑयल 0.8 लीटर, 0.9 लीटर, 1 लीटर और 2.5 लीटर के पैक में उपलब्ध है। इसकी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) 756 रुपये प्रति लीटर है।

अदालतों के कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लेने के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति : फडणवीस



मुंबई। महाराष्ट्र में अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि न्यायालयीन कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे आवश्यक निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री अतिथिगृह में न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित समिति में मुंबई उच्च न्यायालय के महाप्रबंधक, विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। यह समिति उच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेगी और उनके क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद राज्य सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक निर्णय लेगी। फडणवीस ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लेने से पहले शासन के अन्य विभागों और स्तरों पर समान संवर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान, भत्तों और सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। इसके साथ ही प्रस्तावित निर्णयों से राज्य के सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी आकलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई उच्च न्यायालय ने इससे पहले न्यायालयीन कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए दो न्यायाधीशों की समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब नई तीन सदस्यीय समिति पूर्व में दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करेगी। बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई उच्च न्यायालय के महाप्रबंधक शेखर मुघाटे, विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव स्वप्निल खटी, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रमुख सचिव (लेखा एवं कोषागार) ऋचा बागला सहित विभिन्न न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)